भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस

******

अज्ञात वक्ता: कक्ष में उपस्थिति सभी लोगों को मेरा नमस्कार। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर डाल दें। धन्यवाद। पैनल के माननीय सदस्यों, विशिष्ट अतिथियों, देवियों और सज्जनों- ***बांग्लादेश एवं म्यांमार में हुए चुनावों के प्रभावों की व्याख्या***, विषय पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हमारे साथ पैनल में आज जाने- माने विषय विशेषज्ञ हैं और हम अपने वक्ताओं को हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए दिल से उनका धन्यवाद करते हैं।

मैं आज के कार्यक्रम की जानकारी संक्षेप में देना चाहता हूँ। सत्र का आरंभ राजदूत प्रीत मलिक के आरंभिक भाषण से होगा। श्री मलिक म्यांमार में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं और आज के सत्र की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। पहली वक्ता होंगी डॉ. श्रीराधा दत्ता। डॉ. दत्ता जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़, कोलकाता की निदेशक रह चुकी हैं। इसके बाद यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के संपादक श्री जयंत रॉय चौधरी अपने विचार साझा करेंगे। पैनल की तीसरी सदस्य होंगी इंडिया फाउंडेशन की विशिष्ट फेलो सुश्री रामी देसाई। सत्र के अंतिम वक्ता होंगे एशियन कॉन्फ्लुएंस के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची दत्ता। पहले दो वक्ता बांग्लादेश के मुद्दे पर विचार साझा करेंगे। पैनल के तीसरे और चौथे वक्ता म्यांमार पर चर्चा करेंगे। पैनल चर्चा का समापन अध्यक्ष महोदय द्वारा संचालित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सत्र के साथ किया जाएगा।

इसके साथ ही, अब मैं राजदूत प्रीत मलिक से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना आरंभिक भाषण दें और आज की कार्यवाही का संचालन करें। सर, कृपया शुरू करें।

प्रीत मलिक: नमस्कार। यहाँ आ कर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं भारतीय वैश्विक परिषद का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे और इतने अच्छे शिक्षाविदों को आज की चर्चा में शामिल किया है। आपको मुझसे अधिक हमारे पैनल के सदस्यों से सीखने को मिलेगा। मैं भी अच्छा- खासा अनुभव रखता हूँ और म्यांमार में उस समय था जब हालात आज की तुलना में बहुत अलग थे।

आपको उसका केवल परिचय देता हूँ। मुझे वहाँ इस विशेष निर्देश के साथ भेजा गया था कि मैं सरकार के किसी भी मंत्री से किसी प्रकार की मुलाकात नहीं करूँगा। यह 1990 की बात है। उस समय हम यह तय कर रहे थे कि म्यांमार के लिए हमारी कोई नीति है या नहीं। मैंने तीन अलग- अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। हर एक ने मुझे कई बार वापस बुलाया और अंत में, मैं नीति पर कोई विशेष निर्देश दिए बिना चला गया। बाद में नीति में परिवर्तन हुआ और अब हम इस सिद्धांत का सख्ती से पालन करते हैं कि जो लोग सत्ता में हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते रहेंगे।

एक बात जिस पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा, वह यह है कि म्यांमार के चुनाव, जो पिछले साल दिसंबर में शुरू हुए थे और इस साल जनवरी में समाप्त हुए, और बांग्लादेश में फरवरी महीने में अभी कुछ दिन पहले हुए चुनावों में जो हुआ, उसमें एक समानता है। समानता है कि कोई भी चुनाव सबको साथ लेकर नहीं हुआ। यदि आपको याद हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार, दोनों मामलों में, दोनों देशों के मामलों में उस शब्द का उल्लेख किया है।
लेकिन म्यांमार के मामले में, मुख्य राजनीतिक दल, एनएलडी, जो कुछ समय से सत्ता में थी, उसे बाहर कर दिया गया। वास्तव में, न केवल उसे बाहर किया गया बल्कि उसका विघटन भी कर दिया गया। यह अब म्यांमार में एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं है।

अब बांग्लादेश की बात करें तो, हम सब जानते हैं कि अवामी लीग बाहर हो गई थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन एक तरह से, बांग्लादेश में ऐसा होना कोई नहीं बात नहीं थी क्योंकि पिछले कुछ चुनाव स्पष्ट रूप से सबको साथ लेकर चलने वाले नहीं रहे हैं। दोनों देशों के चुनावों में यह एक समानता है, दोनों ही भारत के अनिवार्य पड़ोसी देश हैं। म्यांमार के मामले में, हमारे पास एक और कारक है- श्री ने विन या जनरल ने विन, जैसे कि उन्हें जाना जाता था, के समय से ही म्यांमार पर किसी- न-किसी रूप में सेना का शासन रहा है।

स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, केवल एक बार ही म्यांमार में लोकतंत्र था, वह समय था 1948 में स्वतंत्रता मिलने से लेकर 1960 का समय। वर्ष 1960 में श्री ने विन ने सत्ताधारी सरकार के खिलाफ़ तख़्तापलट किया था। हाल में हुए चुनावों से सैन्य शासन मज़बूत हुआ है, जहाँ सभी प्रभावकारी उद्देश्यों के लिए, वर्तमान जुंटा नेता, सीनियर जनरल मिन ह्लाइंग ने, किसी-न-किसी तरह से, अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है। मैं बस यही बात स्पष्ट करना चाहता था।

बांग्लादेश के मामले में, अब हमारे पास एक निर्वाचित सरकार है जिसने अंतरिम सरकार की जगह ले ली है, जिसके साथ भारत के संबंध बहुत जटिल थे। एक बात से हम इनकार नहीं कर सकते, ये दोनों देश हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी देश हैं- रणनीतिक और सुरक्षा दोनों ही दृष्टि से।

रणनीतिक रूप से, सबसे पहले म्यांमार की बात करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी वास्तव में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अवधारणा के बारे में जानते होंगे। बर्मा या म्यांमार, आज यह इसी नाम से जाना जाता है, एक लैंड ब्रिज का काम करता है जो भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को आसियान से जोड़ता है, मुझे लगता है कि हम कनेक्टिविटी मार्ग बनाकर इसे मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदकिस्मती से अभी तक अधर में लटका हुआ है।

दूसरा हिस्सा म्यांमार के मामले में सुरक्षा का मुद्दा रहा है। हमारे पास भारत के विद्रोही समूह हैं जो म्यांमार की ज़मीन पर सक्रिए हैं, जिन्हें समय- समय पर चीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जातीय समूहों के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है, जिनका म्यांमार में प्रभुत्व है। यह एक बड़ी समस्या है और यदि आने वाले कुछ वर्षों में म्यांमार में स्थिरता नहीं आती तो सुरक्षा का मुद्दा, भारत के लिए सुरक्षा समस्या और बढ़ जाएगी क्योंकि भारत के साथ म्यांमार के सटे हिस्से वास्तव में नेप्यीडॉ (NAPITOR) के नियंत्रण से बाहर हैं।

बांग्लादेश के मामले में, बीएनपी (BNP) पहले वर्तमान नेता की माँ खालिदा ज़िया की माँ की नेतृत्व वाली पार्टी थी, जिनके भारत के साथ बहुत नाज़ुक और मैं तो कहूँगा कि भारत-विरोधी संबंध थे। मैंने बांग्लादेश में सेवाएं नहीं दी हैं लेकिन मैंने बांग्लादेश के साथ काम किया है, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय में अपनी पिछली पोस्टिंग के दौरान, जब मुझे दो- तीन बार बांग्लादेश जाने का मौका मिला था।
उस समय, खालिदा ज़िया प्रधानमंत्री थीं और हमारे संबंध संकटपूर्ण थे। उनके शासन काल में बांग्लादेश में उत्तर- पूर्व के विद्रोही समूह थे जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था, हर तरह की मेहमाननवाज़ी की जा रही थी, और उस इलाके का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किया जा रहा था।

यह एक ऐसी बात है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। क्या बीएनपी का नया नेतृत्व भारत के हितों के प्रति अधिक सहानुभूति रखेगा या वह कमोबेश पुरानी नीति पर ही चलेगा? यह बात उनके सत्ता संभालने के बाद अधिक स्पष्ट होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि हाल ही में हमने एक सलाहकार और बीएनपी के नेता के जो बयान सुने हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि उन्हें भारत के साथ अपने संबंध सुधारने की ज़रूरत है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें संबंधों को सुधारना होगा।

साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे ऐसे संबंध रखेंगे जो उनके लिए लाभकारी हो और इसमें उन्होंने भारत, पाकिस्तान और चीन का नाम लिया है। जहाँ तक उनके संबंधों का सवाल है, वे एक प्रकार का संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, क्या वे भारत को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं? क्या वे भारत के हितों की अनदेखी कर सकते हैं? ये वे मुद्दे हैं जिनसे उन्हें निपटना होगा। भारत नई सरकार से कैसे निपटेगा, जहाँ तक प्रधानमंत्री के नए नेतृत्व का हाल के बधाई संदेशों का सवाल है, उनसे पता चलता है कि भारत नई सरकार के साथ, मान लीजिए, एक मज़बूत संबंध बनाने की कोशिश में तेज़ी से आगे बढ़ा है, यह बहुत ही सकारात्मक है।

तो अब हम वास्तव में क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक तरफ आपके पास म्यांमार में नई चुनी हुई सरकार है, जो मार्च महीने में कभी भी बन जाएगी। मुद्दा यह होगा कि क्या सीनियर जनरल अब म्यांमार के राष्ट्रपति बनेंगे? क्योंकि यह उन मुद्दों में से एक है जिससे नई संसद को निपटना होगा क्योंकि उन्हें एक राष्ट्रपति चुनना होगा। इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। असल बात यह है कि एक बार जब पैनल के सदस्य विस्तार से बात करना शुरू करेंगे तो आपको एक ठीक- ठाक तस्वीर मिल जाएगी कि क्या उम्मीद की जा सकती है।

हालात को समझने के हिसाब से, मुझे लगता है कि वह आदमी कमोबेश देश का बिना किसी मुकाबले का राष्ट्रपति होगा। एक प्रकार से, हम एक जाने-माने आदमी के साथ संवाद करेंगे। हम बीते दो वर्ष से अधिक समय से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, वह एक जाने-माने नेता हैं। बांग्लादेश के मामले में, बेशक, हमारे सामने एक नया नेता है। लेकिन एक ऐसा नेता जिस पर पहले ही भ्रष्टाचार और मनमानी करने का आरोप लगा हुआ है और जो 17 साल से देश निकाला की सज़ा काट रहा था। क्या अब वह एक ऐसा इंसान होगा जो बदल गया है, जिसने अपने अनुभवों से सीखा है, जो एक ऐसे देश के साथ बातचीत के नतीजों को समझ गया है जिसमें ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता?

इसमें एक आर्थिक मुद्दा है। आमतौर पर समाज से संबंधित मुद्दे हैं। इसे युवाओं से भी बातचीत करनी है, एक ऐसा तत्व जो वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आप इस संवाद को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि यह पूर्व प्रधानमंत्री और उनके राज के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व में हुआ विद्रोह था। वे उन्हें सत्ता से बाहर करने में कामयाब रहे।
उन्होंने यह भी किया है, भले ही उन्हें केवल छह सीटें मिली हों या कुछ और, असल बात यह है कि उन्हें अब और नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। उन्हें ध्यान में रखना होगा। मैंने देखा कि श्री तारिक हुसैन ने न केवल जमात-ए-इस्लामी समूह से मुलाकात की बल्कि छात्र समूहों से भी मिले। इससे पता चलता है कि ध्यान दिए जाने वाले उन आवश्यक क्षेत्रों की पहचान की गई है।

मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह केवल एक परिचय है। मैं किसी विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं इसे हमारे पैनल के विशेषज्ञों के लिए रहने देता हूँ। दो विशेषज्ञ म्यांमार पर अपनी जानकारी साझा करेंगें और बाकी के दो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि बांग्लादेश क्या कर रहा है। हम पहले विशेषज्ञों के विचारों को सुनेंगे और फिर चर्चा करेंगें, मुझे आशा है कि विशेषज्ञों के विचारों से हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, वह और स्पष्ट होगी।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पैनल, अब आपकी बारी।

श्रीराधा दत्ता: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं पैनल के सभी सदस्यों को नमस्कार करती हूँ, हम सभी बहुत समय से मित्र हैं। आज की चर्चा में मुझे आमंत्रित करने के लिए अन्वेषा और श्रीपति और निश्चित रूप से आईसीडब्ल्यूए को विशेष आभार देती हूँ।

मैं अध्यक्ष महोदय मलिक जी की बातों से ही शुरू करती हूँ। एक शब्द है 'समावेशी', इसका बहुत प्रयोग किया गया है। चुनावों से पहले, भारत सरकार लगातार बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और समावेशी चुनाव देखने की बात कर रही थी। चुनाव के बाद, बेशक, हमने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है लेकिन इस बात का एक संदर्भ ज़रूर है कि 'समावेशी' शब्द इतना आवश्यक क्यों हो गया है। वास्तव में, जैसा कि आप सभी को याद होगा, बांग्लादेश में आखिरी बार सबको साथ लेकर चलने वाले चुनाव दिसंबर 2008 में हुए थे।

जनवरी 2009 में शेख हसीना ने भारी जीत हासिल करने और सत्ता संभालने के बाद, जल्द ही कुछ बहुत गंभीर सुधार किए, बड़े और गहरे संवैधानिक सुधार, जिससे न केवल बांग्लादेश पहले से कहीं अधिक धर्मनिरपेक्ष दिखने लगा, बल्कि कुछ संवैधानिक संस्थाओं को भी खत्म कर दिया, जिन्होंने असल में इस विशेष समावेशी शब्द समाप्त कर दिया था जिसकी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने इस पहचान को छीन लिया जिसे केतिका सरकार के नाम से जाना जाता है। अब केतिका सरकार ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हों।

यह विश्व के इस हिस्से में हुए कुछ प्रयोगों में से एक है लेकिन बांग्लादेश के लिए यह बहुत अच्छा काम कर रहा है जहाँ सरकार में होने के बावजूद, राजनीतिक दल उस राजनीतिक पार्टी पर विश्वास नहीं करतीं जो सरकार चला रही होती है, इसीलिए आमतौर पर केतिका सरकार बनाई जाती थी जिसके मुखिया सुप्रीम कोर्ट के अंतिम सेवानिवृत्त जज

होते थे। पूरी कैबिनेट तकनीकी विशेषज्ञों से बनी थी, फिर, सबकी सहमति से निर्णय किया गया। सभी दलों ने एक साथ बैठकर यह फैसला किया। वे चुनाव आयोग की मदद करेंगें और उनका कार्यकाल 90 दिनों से अधिक नहीं होता था, इन्हीं 90 दिनों में उन्हें काम करना होता था, चुनाव कराना होता था और वापस जाना होता था।

जब शेख हसीना कई संवैधानिक संशोधन ले कर आईं, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो उन्होंने एक समिति बनाई और उनसे सुझाव मांगे। समिति में पांच सदस्य थे। अवामी लीग के सदस्य, ध्यान रखें, कोई बहु-दल सदस्यी समिति नहीं थी, असल में उन्होंने कहा कि वे इस बात से सहमत हैं कि केयरटेकर सरकार समाप्त कर देनी चाहिए लेकिन अगले दो चुनावों के लिए केयरटेकर होना चाहिए और तीसरे के लिए, वे बाद में फैसला करेंगे। उस संसद सत्र के आखिरी दिन, उन्होंने बिना किसी चर्चा के बिल पास कर दिया, जैसा कि उनकी आदत थी, जैसा कि हमने पिछली कई संसदों में देखा है और बस यही था।

तो 2014 में अगले चुनावों में, बीएनपी (BNP) ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह कभी भी मुफ्त और उचित नहीं होगा, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। वर्ष 2018 में अमेरिका ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह एकतरफा लग रहा है, यह अच्छा नहीं है, कृपया इसे बदलें। तो हमने बीएनपी का अभियान देखा, हमने उनकी थोड़ी दिलचस्पी और लोगों तक पहुँचने की कोशिश भी देखी। फिर, हममें से कुछ लोग जो बांग्लादेश को करीब से समझते हैं, उनके लिए 18 तारीख की सुबह, 11 बजे, बांग्लादेश सरकार ने चुनाव के नतीजे घोषित किए, जिसमें अवामी लीग को भारी बहुमत मिला।

तो फिर मैंने दोस्तों से बात किया कि आखिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हममें से कोई नहीं, और मेरे कई दोस्त हैं जो इतने सालों से इस देश की स्थितियों पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं, साल में कम- से-कम चार बार वहाँ जाते हैं, यदि उससे अधिक नहीं, तो स्पष्ट है कि हमने वहाँ कई संपर्क स्थापित किए हैं और दोस्ती बनाई है। जिनसे भी मैंने बात की, उन सभी ने कहा कि हम मतदान केंद्रों पर गए थे, हमें केंद्र में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। स्पष्ट है कि सब कुछ पहले से, एक रात पहले ही तय कर लिया गया था।

और फिर बेशक हमने 2012 में देखा, मैं 24 जनवरी, चुनाव के दिन, ढाका में थी, और मैंने कहा था कि मैंने अवामी लीग को अवामी लीग के लिए वोट करते नहीं देखा क्योंकि वास्तव में अवामी लीग, बहु- दलीय पार्टियां, अलग- अलग नामों से फैली हुई थीं लेकिन इनमें से लगभग शून्य था, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कहा था कि 15% मतदान हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अधिक उदारता दिखा दी थी। निश्चित रूप से फिर हम सबने देखा कि क्या हुआ, युवाओं का विद्रोह।

जैसा कि हमने देखा है, अंतरिम सरकार के बारे में कई दौर की चर्चाएं और बहसें हुईं। मैंने, फिर से उस जगह पर थोड़ा ध्यान दिया है, अंतरिम सरकार के आने के बाद से मैं तीन बार बांग्लादेश गई हूँ। मेरा पूरा मानना है कि यह आंदोलन, बेशक, नीचले स्तर से ऊपरी स्तर तक का था। फिर अन्य हितधारकों को भी शामिल किया गया क्योंकि मैं अक्सर जमात के नेताओं से मिलती हूँ और मुझे याद है कि इस बारे में कई बार बातचीत हुई थी लेकिन मुझे डॉ. ताहिर भी याद हैं, जिनसे मैं वास्तव में मिली थी, जो जमात के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने कहा था- नहीं यह एक आंदोलन

है जिसे हमने शुरू किया था। असल में यह हर एक राजनीतिक दल का शुरू किया हुआ आंदोलन था, चाहे वह बीएनपी हो, जमात हो या कोई और। लेकिन यह छात्रों का आंदोलन था।

निश्चित रूप से, अमेरिकी लिंक के बारे में पता है और इन सबके बारे में भी पता है लेकिन मैं देख रही हूँ कि आंदोलन नीचले स्तर से शुरू हुआ था। फिर, हमने देखा कि क्या हुआ, यह किस तरह से सामने आया और फिर 5 अगस्त की घटना हुई। जब से अंतरिम सरकार बनी है, हमने बांग्लादेश में बहुत हिंसा देखी है। भीड़तंत्र शब्द का प्रयोग हम अक्सर करते थे। असल में, बांग्लादेश में जो पहली भीड़तंत्र वाली घटना हुई, वह असल में उन नौकरशाहों ने की थी जिन्हें पिछली सरकार में अवामी लीग ने निकाल दिया था। उनमें से सौकड़ों लोग सचिवालय के पास इकट्ठा हो गए, उनमें से कईयों की नौकरी बहाल की गई।

बांग्लादेश में हमने जो भीड़तंत्र देखा, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। कक्षा 9 के छात्रों ने कहा, हमारी बोर्ड की परीक्षा की तारीखें बदलो। कक्षा 12 के छात्रों ने कहा, अभी परीक्षा नहीं करानी चाहिए। हमें हमारी फाइनल मार्कशीट पिछली कक्षा की परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर दी जानी चाहिए। बहुत सारे देशद्रोही, बनी-बनाई सरकारें, बस आप नाम ले लें। ऐसी ही स्थिति थी। लेकिन हमने कमज़ोर तबके, जैसा कि वे इसे कहते हैं, को भी बहुत लक्षित होते देखा, लेकिन अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं को।

तो हममें से कई लोगों के लिए जो दिल्ली से, और विशेष रूप से दिल्ली और भारत के अलग-अलग हिस्सों से स्थिति पर नज़र बनाए हुए थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस बात के बावजूद विदेश सचिव गए और वापस आकर संसद में बहुत सकारात्मक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार भारत के साथ काम करने को तैयार थी लेकिन उनका एक अनुरोध था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोई राजनीतिक बयान नहीं देने दिया जाए। उन्होंने संसद में यह कहा लेकिन स्पष्ट है कि हमने इसका उलटा देखा है। हमारा दावा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है।

लेकिन बांग्लादेश में चुनाव से ठीक दो सप्ताह पहले, पूर्व मंत्रियों ने दो मीडिया कार्यक्रम किए, जो उस दमनकारी आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा थे जिसे हमने तब देखा था जब छात्रों, जैसा कि मैंने बताया, कोटा आरक्षण के खिलाफ़ पूरी तरह से बिना हथियार वाला छात्र आंदोलन था। मुझे लगता है कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी है, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊँगी, जिसे तब अवामी लीग सुरक्षा बल ने बहुत सख्ती से संभाला था। निश्चित रूप से, अब, एक दिन पहले, मुझे लगता है कि हसन ने एक और साक्षात्कार में कहा है कि- सुरक्षा बलों ने वही किया जो उन्हें करना था। मेरी माँ का इस मामले से कोई लेना- देना नहीं था।

हमने इस तरह की कई घटनाएं देखी हैं। लेकिन बीते 18 माह में, बांग्लादेशियों के भीतर ही इस बात को लेकर बहुत डर था कि चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें लगा और यह बहुत लोकप्रिय बात है, जिसे भारत में भी समर्थन मिलता है कि प्रोफेसर यूनुस सत्ता से बाहर नहीं होने जा रहे। चुनाव नहीं होने वाले हैं। यब सब मज़ाक भर है। असल में, बांग्लादेश में मेरे और अन्य पैनल चर्चाओं में मेरे कुछ मित्र थे जो कह रहे थे कि- सेना कब्ज़ा कर रही है। यह देश

बर्बाद हो जाएगा। मैं एक बांग्लादेशी की राय की बात कर रही हूँ। बेशक, बीते 18 माह में सीमा के दोनों तरफ से गलत जानकारी वाली बातें, मीडिया में चल रही बातें बहुत अधिक देखने को मिली हैं।

उन्होंने आपको गलत धारणा देने के लिए एआई का अच्छे से प्रयोग किया है। लोग सीधे-सादे हैं। हम उन पर ह्वाट्सऐप खबरों में से कई खबरों के झांसे में आ गए जो हमें मिलीं। इसलिए जब मैं योजना बना रही थी, तब मैं भारत से एकमात्र विदेशी चुनाव पर्यवेक्षक थी। बाकी जाने वाले लोग मीडिया प्रतिनिधि थे। बांग्लादेश में लगभग 650 लोग गए थे, जिसमें 400 मीडिया पर्यवेक्षक और 250 चुनाव पर्यवेक्षक थे जिन्हें बांग्लादेश की सरकार ने आमंत्रित किया था। यहाँ से जाने वालों में मैं अकेली थी। मैं अभियान नहीं देख पाई लेकिन मैं मुख्य चुनाव आयोग की पहली प्रेस मीडिया सम्मेलन में शामिल थी। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि आप सब कहीं भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। आप लाइव टीवी करना चाहते हैं, लाइव पॉडकास्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है इसलिए आप कहीं भी बेझिझक पहुँच सकते हैं।

जब मैं अपने दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए हस्ताक्षर करवाने जा रही थी, और मैंने कहा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। मैं केवल ढाका में ही रहूँगी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पूरे बांग्लादेश के लिए बना रहा हूँ, आपका मन करे तो आप जा सकती हैं। हम लोगों को बांग्लादेश के हर एक हिस्से में जाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने बीते जनवरी में अबा मिलिगर के चुनावों में कुछ दिन वहाँ गुज़ारे थे। यहाँ मेरा अनुभव बहुत अलग था। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, जनवरी'24 में सड़कों पर कोई नहीं उतरा। इस बार, मैं सड़कों पर उतरी। गली-गली गई। मतदान सुबह 7.30 बजे से शुरू हुए। मैं सुबह 9.30 से निकल गई थी। मतदान केंद्र 4.30 बजे शाम को बंद हो गए। मैं शाम 6 बजे तक गली- गली घूमती रही।

जिस तरह की खुशी और उल्लास था और डर का माहौल था, हमने हमेशा यही सोचा था कि अगर चुनाव हो भी रहे हैं तो यह हिंसा से भरा होगा। हमने बच्चों को सड़कों पर खेलते देखा, असल में, ढाका में मैंने जितने भी मतदान केंद्र देखे, वे ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के कैंपस में बनाए गए थे। आपके पास खेल का मैदान था। बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। हवा में गुब्बारे उड़ाए जा रहे थे। और हाँ, हर एक केंद्र पर, काश मैं आपको तस्वीरें, गुब्बारे, रंग- बिरंगे गुब्बारों की तस्वीरें दिखा पाती। मैंने हमेशा यही पाया है। बहुत साल पहले, मैं एक बार बांग्लादेश गयी थी। मैंने देखा कि चुनाव के दिन कितने खुशनुमा होते थे। वे गाते थे, झूमते थे। हर तरफ फूल खिले होते थे। मैंने इस बार बहुत सारे फूलों को खिले नहीं पाया। इस बार गुब्बारे अधिक थे। लेकिन माहौल बहुत खुशनुमा था।

वास्तव में, मैं क्या कह रही हूँ, जब चुनाव हुए तो हमने एक विश्वसनीय, सुरक्षित माहौल देखा। मुझे लगता है कि हर एक पर्यवेक्षक ने कहा है कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र एवं उचित थे। इस बारे में कोई सवाल नहीं उठा। फिर हमने देखा कि घोषित 299 सीटों में से, उन्हें 212 बीएनपी (BNP) और 78 जमात को मिलीं। मुझे लगा कि यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है क्योंकि यदि आप ढाका को ही देखें तो यह लगभग आधा- आधा है। मेरे कहने का मतलब है, बीएनपी के लिए थोड़ा ज्यादा लेकिन जमात को भी सीटें मिली हैं। हमने हमेशा यही सोचा है कि शहरी, आधुनिक बांग्लादेशी जमात को वोट नहीं देते। लेकिन मैं तब भी वहीं थीं जब जमात ने पहली बार, शिबिर, जो जमात का एक

छात्र समूह है, अपने छात्र संघ चुनाव, डैक्सो चुनाव करवाए थे। मैं उस सप्ताह में वहीं थीं। मैं चुनाव के दिन भी वहीं थी। मैंने देखा कि उन्होंने कैसे खुद को फिर से तैयार किया है।

निश्चित रूप से, जमात में अब कई महिलाएं भी हैं, और मैं इस बारे में मज़ाक भी करती रहती हूँ कि आप केवल उनकी आँखें देख सकते है। बाकी सब बहुत करीब से जुड़े हुए हैं लेकिन बहुत सारे, बहुत सारे नौजवान भी हैं जो रेग्युलर जींस पहन कर इसका हिस्सा बने हैं। मैं कहती रहती हूँ कि तारिक रहमान की सफ़ेद शर्ट और नीली जींस देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। वह अपने पूरे अभियान के दौरान यही पहनते रहे हैं। जमात के नौजवानों ने खद को वर्तमान समय के अनुरूप बनाया है। मेरा मतलब है, मेरे पास विस्तार से बताने का समय नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो मानना चाहता हूँ और मैं इसे लेकर बहुत खुश हूँ कि उन सभी ने अतीत से सबक लिया है। जिस बात का उल्लेख राजदूत मलिक ने भी किया, उससे हम अब भारत के लिए इसे कैसे देखते हैं?

जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कुछ ही मिनटों में हम वहाँ कैबिनेट को शपथ लेते हुए देखेगें। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को विदेश मंत्री बनाया जाना दिलचस्प है। वह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वे नियमित सांसद नहीं हैं लेकिन उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। बाकी सभी ने बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है। कुछ सीटों पर, और यह बहुत दिलचस्प है, बेशक, बहुत कड़ी टक्कर हुई है, और कई सीटों पर, विशेषरूप से ढाका में। ढाका में कुछ सीटें हैं, जिनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि एक्ट नियंत्रण करता है। यदि ढाका की सीटों पर सरकार बनाने वाली पार्टी जीतती है तो पूरे बांग्लादेश पर उसका नियंत्रण होता है।

बहुत करीबी मुकाबला रहा। एक सांसद तो केवल 1,000 वोटों के अंतर से जीते, केवल 1,000 वोट। लेकिन 2,000 वोटों के अंतर से जीतने वालों की संख्या बहुत अधिक रही। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी कि भारत के लिए यह कैसे बदलेगा? अभी तक, हमने कुछ बहुत ही नरम रवैया पाया है, न केवल बीएनपी की तरफ से बल्कि ज़मात- ए- इस्लामी की तरफ से भी। जैसा कि मैंने कहा, मैं उनके कुछ बार मिली हूँ, और मैंने बताया, अच्छा, आपके 71 के बारे में क्या? फिर आपका भारत- विरोधी एसोसिएशन। उन्होंने कहा, अच्ची बात है, हमने अपनी गलतियों से सबक लिए हैं। हम समझते हैं कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। हमने इस पर बात की है, हमारे नेताओं ने इस बारे में बात की है। इसलिए मुझे काफी उम्मीद है। निश्चित रूप से कई मुद्दे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक का मुद्दा कितना बड़ा है।

मैं अभी संयुक्त सचिवों में से एक हुमायूं कबीर का साक्षात्कार सुन रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि समस्याएं दोनों देशों में हैं। चलिए ऐसा न मानें कि यह केवल एकतरफ़ा समस्या है। हमारे पास पानी की समस्या है जिन पर आपने बात नहीं की है। तो वर्तमान में, हमारे पास गंगा जल संधि है जो 30 वर्ष हो गए हैं, आने वाले कुछ महीनों में इस संधि का नवीनीकरण किया जाना है। हमारे पास तीस्ता है, जो फिर से नाज़ुक स्थिति में है। जैसा कि आपको याद होगा, इस बीच, तीस्ता प्रबंधन परियोजना, जिसे शेख हसीना ने, वास्तव में उनकी कैबिनेट ने तैयार किया था, लगभग चीन को दिया जा रहा था लेकिन इसे एक प्रकार से रोक दिया गया है।

मुझे आशा है कि भारत इस मुद्दे पर ध्यान देगा। निश्चित रूप से, हसीना एक कारक हैं। मुझे लगता है कि वे सभी समझते हैं और सहमत हैं कि हसीना भारत के लिए बहुत सम्मानित मेहमान हैं। इसलिए प्रत्यर्पण कोई विकल्प नहीं है। यहाँ बात यह है कि क्या भारत उसे ये राजनीतिक गतिविधि करने देगा। जिन दो घटनाओं की मैं बात कर रही हूँ वे निश्चित रूप से....मेरे कहने का मतलब है, भारत सरकार के बिना मुमकिन नहीं होतीं। मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना होगा।

जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने कहा है कि... तारिक ज़िया अपनी बात पर अमल कर पाते हैं या नहीं, यह हमें देखना होगा क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो हर देश में कई स्तर होते हैं, जिसमें नौकरशाही भी शामिल है, जिनका दृष्टिकोण अलग होता है, बिल्कुल अलग नज़रिया होता है। तारिक रहमान के लिए यहाँ सबसे पहली चुनौती कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। हमने पुलिस बल को देखा है, जो बहुत बदनाम बल रहा है क्योंकि हसीना के समय में उसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ था। इसलिए उस बल को आधा- अधूरा बदला गया है, पूरी तरह से नहीं। यह बहुत ज़रूरी बात है।

कानून और व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता। शेख हसीना के समय में इस बात के बावजूद कि हम हमेशा बांग्लादेश की शानदार विकास कहानी के बारे में बात करते हैं, नहीं, बांग्लादेश धीरे- धीरे और लगातार बुरी स्थिति में जा रहा था जिसके बारे में हम कभी बात नहीं कर रहे थे। इसलिए अंतरिम सरकार ने इसे ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे 15, 18 महीने में दूर कर लिया जाए। यह कुछ ऐसा है जो बीएनपी सरकार को करना होगा। ज़ाहिर है घरेलू मामले उनकी प्राथमिकता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है भारत उनका सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है।

आपका हर एक बयान, चाहे वह ज़मात के मुखिया शफ़ीक-उर-रहमान का हो या बीएनपी का हो, इस पर आता है। दोनों तरफ झगड़े के मुद्दे हैं लेकिन मुझे लगता है कि इरादा नेक होने पर, मुझे उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश, अपने संबंधों को फिर से बेहतर बना सकते हैं, उन्हें अपने संबंधों को रीबूट करने की आवश्यकता है। मेरे विचार में हमारे लिए बांग्लादेश तक पहुँचना ज़रूरी है।

मुझे उम्मीद है कि यह एक स्थिर सरकार होगी। यह एक ऐसी सरकार होगी जिस में हम देखेंगे कि विपक्ष वास्तव में दबाव डाल पाएगा। केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि पहली बार वोट डालने वाले 40% मतदाता, जो 18 से 38 वर्ष के बीच के थे, बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखेंगे। बांग्लादेश में हमेशा से ही एक बहुत मज़बूत नागर समाज रहा है और मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में विपक्ष और सरकार दोनों ही ज़िम्मेदार साझीदार होंगे। हमें आशा है कि बांग्लादेश के आने वाले दिन अच्छे होंगे। धन्यवाद।

जयंत रॉय चौधरी: धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरी दोस्त श्रीराधा ने शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बारे में लगभग हर एक बात पर रौशनी डाली है। निश्चित रूप से उन्होंने इन 18 महीनों में मौजूद भीड़तंत्र का भी उल्लेख किया है। बदकिस्मती से, छात्र विद्रोह जिस भी कारण के लिए खड़ा हुआ, चाहे वह कितना भी लोकप्रिय या अलोकप्रिय रहा हो, इन 18 महीनों में वह बहुत अधिक अलोकप्रिय हो गया। भीड़ सड़कों पर होती थी, जबरन वसूली

की जा रही थी, कुछ बीएनपी के कैडर ऐसा करते थे, कुछ दूसरों के करते थे और कहीं लक्षित हत्याएं होती थीं, शैक्षणिक समुदाय के लोगों और सिविल सेवा में कार्यरत अधिकारियों से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जाता था।

तो एक पार्टी को इससे लाभ हुआ, पार्टी थी- जमात, वे अपने लोगों को शैक्षणिक समुदाय में शामिल करने में कामयाब रहे, वे बहुत से लोगों को सिविल सर्विस में भी लाए। दक्षिण एशिया में चुनाव ज्यादातर शिक्षक ही करवाते हैं, नौकरशाह उतने नहीं होते। निचले स्तर पर शिक्षक ही होते हैं जिन्हें चुनाव अधिकारी, मतदान केंद्र अधिकारी आदि बनाया जाता है। इसका असर पड़ता है। आइए देखते हैं कि इन 18 महीनों में क्या हुआ। शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश को एक विशेष आर्थिक स्तर पर ला दिया था, जहाँ वह मध्यम स्तर पर आने वाला था, वह कम विकासशील देशों की सूची से बाहर आने की स्थिति में था। बदकिस्मती से, फिर कोविड आया और फिर कपड़ा क्षेत्र में बांग्लादेश के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई।

बांग्लादेश के लिए हमेशा से समस्या यह रही है कि वह केवल एक उद्योग, कपड़ा उद्योग से जुड़ा रहा है। उन्होंने नए उद्योग लाने की कोशिश की, जहाज तोड़ना, जहाज बनाना, चमड़ा आदि लेकिन सच कहूँ तो यह विश्व के लिए दर्जी जैसा ही रहा। एक बार जब आपके दर्जी का काम कम हो जाए तो जीडीपी का विकास कम होने लगा। लेकिन इन 18 महीनों में यह बहुत गिर गया। विद्रोह के दौरान फैक्ट्रियों को जला दिया गया, उनमें से कुछ अहमदिया लोगों की थी, इसलिए उन्हें जला दिया गया क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। जिन फैक्ट्रियों के मालिकाना हक कथित रूप से अवामी लीग के लोग थे, उन्हें भी जला दिया गया। आपके सामने जो आया उसे विऔद्योगीकरण (de-industrialization) कहते हैं।

इसके अलावा, अमेरिका, यूरोप और जापान के खरीददार चले गए। उन्होंने कंबोडिया का रुख किया, भारत का रुख किया। वास्तव में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि झारखंड में 5,000 करोड़ रु. की लागत से एक फैक्ट्री लगाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन बांग्लादेशी उत्पादकों की जगह लेना है जो सीधे यूरोपियों को सामान बेच रहे थे। हर कोई आपूर्ति का ऐसा स्रोत चाहता है, जो स्थिर हो, जो राजनीतिक रूप से स्थिर हो, जिसमें किसी भी तरह सी समस्या से बाधा न आए। तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या बन गई। इन 18 महीनों में आर्थिक गिरावट के दौरान हर महीने इनकी मुद्रास्फीति 8% से अधिक थी। कुछ महीनों में तो यह दो अंकों में भी रही।

अब यह कुछ ऐसा है जो आम लोगों को मंज़ूर नहीं है और इसलिए आपको यहाँ भीड़तंत्र के अलावा बहुत अशांति थी, इसके अलावा आम छोटे व्यापारी और गांव के छोटे दुकानदारों से जबरदस्ती वसूली होती थी। स्थिति खराब थी। जहाँ तक यूनुस सरकार की बात है, यह समस्या थी। यह दाग है, बदकिस्मती से, यूनुस को अपने कंधों पर एक ऐसे आदमी को उठाना पड़ेगा जिसने नोबल शांति पुरस्कार जीता था, जो भारत में भी हीरो था, उन्हें इस समस्या का सामना करना होगा।

अब चुनावों पर नज़र डालते हैं। बांग्लादेश में कभी भी बहुत मज़बूत चुनाव नहीं हुए, चाहे बीएनपी हो या अवामी लीग। सबसे अच्छे चुनाव 2008 में हुए थे, मेरी दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल में वह सबसे अच्छे चुनाव थे। वह ऐसा समय था जब 80% मतदान हुआ था। इस चुनाव के आधिकारिक नतीजे 59.44 हैं, इसका मतलब है कि

यदि आधिकारिक नतीजे मान लिए जाएं तो 20% की गिरावट आएगी। स्वतंत्र विश्लेषक और मैं पार्टी के विश्लेषक की बात नहीं कर रहा, बीएनपी या अवामी लीग का कोई, जैसे कमल हैं, वे कह रहे हैं कि शायद असल मतदान बहुत कम हुआ था, करीब 40%।

अगर हम उस हिसाब से न भी चलें, यदि हम 59.44% के नतीजों को भी देखें, तो भी 20% की गिरावट है। इससे हम दूसरी बात पर आते हैं, अवामी लीग को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यदि शेख हसीना के अभियान के बाद मतदान में इतनी गिरावट आती है, कोई मतदान नहीं, कोई मतदान नहीं, इसका मतलब है कि अवामी लीग अभी भी है, उसे अभी भी समर्थन है। दूसरी बात, हम सब जानते हैं, बांग्लादेश के अखबारों ने भी यह माना है कि अवामी लीग के समर्थन ने बीएनपी के पक्ष में रणनीतिक मतदान की जिससे बीएनपी को बढ़त मिली। वर्ष 2008 में जब यह 22.5% था, अब यह 49.97% मतदान है। तो यह लगभग 18% की बढ़त है।

तो वे कह रहे थे, ये अवामी लाग के समर्थक हैं, मतदान करने वालों में अल्पसंख्यक इस चुनाव में सबसे पहले थे, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने मतदान नहीं किया तो उन्हें समस्या का सामना करना पड़ेगा। समस्या से मेरा मतलब है आम तौर पर होने वाले हमले, हमने पहले भी ऐसे हमले देखे हैं, चाहे कोई भी पार्टी आई हो। यह एक और बात है जिस पर ध्यान देना होगा। जमात-ए-इस्लामी, मुझे यकीन है कि जमात-ए-इस्लामी ने अपनी गिनती बढ़ाई होगी, लेकिन चलिए आंकड़े देखते हैं। वर्ष 2008 में 4.7% और आज 31.76% है। इससे पहले इसका सबसे अच्छा आंकड़ा 1991 में था, जब इसे 12% लोकप्रिय मत मिले थे।

वह तब था जब वह बीएनपी (BNP) के साथ गठबंधन में था। इस बार वह बीएनपी के साथ गठबंधन में नहीं है, वह विपक्ष के साथ है। यह 31.76% बढ़ गया है, बेशक, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, जमात दावा कर रही है कि बीएनपी ने मत-पेटी में धांधली की है। बीएनपी ने भी दावा किया है कि जमात ने मत-पेटी में धांधली की है। इसलिए हम इस बात पर नहीं जाएंगे कि कौन सही है, कौन गलत, लेकिन दोनों तरफ से आरोप हैं। असल में, एक समय तो जमात लगभग चुनावों को खारिज करने जैसा लग रहा था और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। यह एक और मुद्दा है।

एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जमात ने पश्चिम बंगाल से सटे सभी सीमावर्ती जिलों में जीत हासिल की है। असम से सटे कुछ सीमावर्ती ज़िलों में, सभी नहीं, कुछ में। यह ऐसा तथ्य है जिसका ध्यान भारतीय सुरक्षा योजनाकर्ताओं को अपनी योजना बनाते समय रखना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि छात्र विद्रोह के दौरान जेलों को खाली कर दिया गया था। जिन आतंकवादियों पर आंतक से जुड़े आरोप थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे, उनमें से कुछ तो नामित आतंकवादी भी थे, उन्हें रिहा कर दिया गया था। उनमें से किसी को भी गिरफ्तार कर वापस जेल में नहीं डाला गया। माना जाता है कि वे फिर से एकजुट हो गए हैं, उन्होंने वहाँ खुद को दोषमुक्त करवा लिया है।

अगर ये समूह सुधर रहे हैं और अगर सरकार कमज़ोर बनी हुई है, हम कुछ भी कह लें बांग्लादेश की सरकारें हमेशा से कमज़ोर रही हैं। ढाका की सरकार का हुक्म वास्तव में पूरे बांग्लादेश में नहीं चलता इसलिए बांग्लादेश एनजीओ आंदोलन इतना मज़बूत रहा है, इसलिए ग्रामीण बैंक, बीआरएसी (BRAC), ये सब बने हैं क्योंकि सरकार वो नहीं कर

पाई जो उसे करना चाहिए था, इसलिए एनजीओ आए और वो सारे काम करने लगे। इसलिए सरकार को सबको नियंत्रित करने की क्षमता बहुत, बहुत ही कम है। यह चुनौती हर समय बनी रहेगी।

तो सबसे पहले, तारिक रहमान के सामने एक चुनौती है, अर्थव्यवस्था, जो उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। दूसरी, जो उतनी ही ज़रूरी है, वह है कानून और व्यवस्था को फिर से बहाल करना। उन्होंने कहा है कि ये दो बातें हैं जिन पर मैं वास्तव में चर्चा करने वाला हूँ और मुझे आशा है कि इन मुद्दों का समाधान कर लिया जाएगा। उनके लिए समस्या जमात होगी क्योंकि जमात अब इस चुनाव के साथ- साथ कई मुद्दों पर एक और गोनो वोट या जनमत संग्रह की मांग करने जा रही है जिन्हें हम मोटे तौर पर चार मुद्दों में बांट सकते हैं।

असल में किसी को नहीं पता था कि 'हाँ' वोट का क्या मतलब है। यदि वे दो के लिए राज़ी थे, तो क्या वे बाकी दो के लिए भी राज़ी थे? क्या उन्होंने केवल दो के लिए हाँ में मतदान किया है या दो के लिए नहीं में मतदान किया है, क्योंकि उन्हें दो पसंद नहीं आए? इस बारे में कोई भी ठीक- ठीक नहीं बता सकता। यह कुछ ऐसा है जिससे अब बीएनपी को निपटना होगा। उन सभी ने अब कसम खाई है कि वे न केवल संसद के सदस्य बनेंगे बल्कि वे बांग्लादेश के लिए सुधार आयोग, संवैधानिक सुधार आयोग बनाने की भी कसम खा रहे हैं जिसका मतलब है कि वे इन सुधारों पर चर्चा करेंगे।

मुझे लगता है कि बीएनपी अपनी पसंद के हिसाब से फैसला करेगी। बीएनपी सुधारों के उन हिस्सों को लेगी जिन्हें जनमत संग्रह के लिए रखा गया था, और जिनसे वे सहज हैं। लेकिन वे वह सब कुछ स्वीकार नहीं करेंगें जो जमात जनमत संग्रह के माध्यम से चाहती थी। याद रखें, जनमत संग्रह यूनुस सरकार की तरफ से था और उस समय यूनुस सरकार पर जमात और दूसरी पार्टियों का बहुत अधिक प्रभाव था, जिसमें एनसीपी भी शामिल थी, जो इस चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उनके कुछ बड़े नेता असल में निर्वाचित नहीं हुए थे। कुछ निर्वाचित हुए हैं। वे अभी भी अच्छा रसूख रखते हैं।

जैसा कि राजदूत सर ने कहा, आगे की बातचीत में एनसीपी को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन यह जंग की बांग्लादेश का मानस क्या होगा, बांग्लादेश कैसा होगा? क्या यह एक इस्लामी मुल्क होगा? क्या इसमें प्रधानमंत्री के लिए दो कार्यकाल होंगे और तीसरा कार्यकाल नहीं होगा? यह सब इसी संसद में तय होना है जिसका मतलब है कि जमात के गठबंध के 77 सांसद 212 सांसदों से मुकाबला करेंगे लेकिन केवल संसद के भीतर ही नहीं क्योंकि जमात के पास कूचे का इख्तियार अधिक है, इसलिए यह जंग सड़कों पर भी हो सकती है। इसकी भी संभावना है।

अब अवामी की बात करते हैं, अवामी इस चुनाव का गुप्त लेकिन बड़ा कारक है। यदि बीएनपी जीती है तो उसे अवामी लीग को धन्यवाद करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बीएनपी और अवामी के बीच कोई सौदा हुआ था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरे पास इसे जानने का कोई तरीका भी नहीं है, मैं केवल एक पत्रकार हूँ इसलिए मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपने इलाके में क्या किया होगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी है तो यह एक नीतिगत मामला होगा। क्या आवामी लीग को मैदान में उतरने दिया जाएगा? उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है,

उसे चुनावों में प्रतिबंधित किया गया है, तो आदर्श रूप से कहें तो उन्हें आने देना चाहिए, वे आएंगे या नहीं, यह फिर से जमात और बीएनपी को तय करना होगा क्योंकि इस पर जमात की भी अपनी सम्मति होगी।

चलिए देखते हैं कि यह कैसे आगे बढ़ेगा, यदि उन्हें इजाज़त नहीं दी गई तो हमें याद रखना होगा कि आबादी का एक ऐसा हिस्सा होगा जो वर्तमान में जारी घटनाक्रम से खुश नहीं होगा। हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, यह समझने के लिए कि 1930 के दशक में भी उस समय के बंगाल में दो प्रकार की विचारधारा थी। मुस्लिम बंगालियों के लिए दो पार्टियां थीं- एक थी मुस्लिम लीग जिसे ढाका के नवाब ने बनाया था और दूसरी थी प्रजाकृषक पार्टी जो किसानों के अधिक समर्थन में थी, मैं इसे सच में समाजवादी पार्टी नहीं कहूँगा लेकिन यह निश्चित रूप से फज़लुल हक के नेतृत्व में किसानों के अधिक समर्थन में थी, फज़लुल हक बंगाल के प्रमुख राजनेता थे, उन्होंने बंगाल को एक करने की कोशिश की, उन्होंने सुहरावर्दी से भी बात की, उन सभी ने संयुक्त बंगाल या एक बंगाल के लिए प्रयास किए लेकिन बात नहीं बनी, न तो जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और न ही कांग्रेस इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार थी, और न ही बंगाल इसे मानने को तैयार था, इसी वजह से बंगाल का बंटवारा हुआ था।

फजलुल हक तब तक 1940 में मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके थे, वे पाकिस्तान के प्रस्तावक थे, जी हाँ, मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात पूरी करने वाला हूँ। जल्दी से बता दूँ, वे अवामी बन गए, तो विचार की दो धाराएं बनी रहेंगी और तीसरी जमात है। हम यह नहीं कह सकते कि हम एक विचार की धारा से छुटकारा पा लेंगे और उस देश को चलाते रहेंगे, यदि वह देश चलता रहा तो उस देश में भी समस्याएं होंगी और बांग्लादेश में जो भी समस्याएं पहले से हैं, उनमें इजाफा हो जाएगा, इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें किसी प्रकार की समझ विकसित करनी होगी और तीनों राजनीतिक खिलाड़ियों को अपनी- अपनी भूमिका निभाने देनी होगी, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो समस्याएं आएंगी।

हसीना को वापस लाना तारिक रहमान के लिए समस्या है, वह फंस जाएंगे, यदि वह उन्हें जेल में डालते हैं या फांसी पर लटकाते हैं तो उन्हें समस्या होगी, यदि वह उन्हें राजनेता बनने देते हैं तो भी समस्या होगी, हसीना का भारत में रहना रहमान के लिए राहत की बात है। धन्यवाद।

रामी निरंजन देसाई: नमस्कार। सबसे पहले मैं श्रीपति, अन्वेषा, आईसीडब्ल्यूए को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरा सच में मानना है कि बांग्लादेश और म्यांमार को अलग- अलग देखने के बजाय एक साथ देखा जाना चाहिए। पैनल में बैठे मेरे माननीय मित्र ने अभी- अभी बांग्लादेश के बारे में बात की और मुझे बहुत सी मिलती-जुलती बातें दिखीं जिनके बारे में मैं बात करूँगी। लेकिन मेरे पास अपने विचारों को साझा करने के लिए मात्र 10 मिनटों का समय है और म्यांमार में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। एक बड़ा अवसर जो मुझे अध्यक्ष महोदय ने दिया है। सर आपकी अनुमति के साथ अब मैं शुरू करना चाहूँगी।

श्रीपति ने मुझे तीन मुद्दों पर बोलने के लिए कहा है। मुझे चुनाव के बारे में बोलने के लिए कहा गया। मुझे ईओ और भविष्य के बारे में बात करने के लिए कहा गया था कि मैं इसे कैसे देखती हूँ। मैं इसी मुद्दे पर बनी रहूँगी क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। चुनावों का बहुत इंतज़ार था क्योंकि ये तख़्तापलट के बाद हुए थे और

दाव आंग सान सू की की गिरफ्तारी की वजह से तख़्तापलट की बहुत चर्चा हुई थी। मुझे जनवरी के आखिर में समाप्त हुए चुनावों के तीसरे फेज़ में एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनने का मौका मिला।
मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ लेकिन ये चुनावों पर पूरी तरह से मेरे अपने विचार हैं। लेकिन आपको एक विचार देने के लिए, लगभग 64 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, छह राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थीं और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां थीं। 4,900 उम्मीदवारों ने अपनी वर्दी, सेना की वर्दी उतारकर चुनावों में हिस्सा लिया। यूएसडीपी (USDP) सबसे पसंदीदा थी, म्यांमार को देखने वाला कोई भी यही सोचता था कि यूएसडीपी (USDP) सत्ता में आएगी। यह पहले सेना के समर्थन वाली पार्टी थी।

हमने यह भी देखा कि ये सभी बातें सच हुईं क्योंकि यूएसडीपी (USDP) 81% से जीती। लोअर हाउस, 262 में से 232 सीटें, अपर हाउस 157 में से 109 सीटें। लगभग 67 चुनाव क्षेत्रों में वे चुनाव नहीं लड़ सके, उनमें से कुछ को यहाँ- वहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में इस पर आऊंगी, क्योंकि हमारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वे उन 67 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव क्यों नहीं लड़ सके और अब आगे क्या होगा।

अब हर कोई अंदाज़ा लगा रहा है कि क्या होने वाला है, राष्ट्रपति कौन होगा, जनरल मिन आंग ह्लाइंग क्या करने वाले हैं। पहली अप्रैल तक, वे एक राष्ट्रपति चुन लेंगे और उससे पहले तीन उप- राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे क्योंकि ह्लुटाव, जैसा कि संसद को कहा जाता है, बैठेगा। एक उप-राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। एक का चुनाव निर्वाचित सांसद करते हैं। और एक उप-राष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त ह्लुटाव चुनते हैं।

अब, जब मैं वहाँ थी, यह बहुत ही दिलचस्प था। कुछ देशों के पर्यवेक्षक वहाँ आए थे। नेपाल के चुनाव आयोग के अध्यक्ष वहाँ आए थे। वहाँ बेलारूस के अधिकारी थे। कम्बोडिया जैसे कुछ और देशों के प्रतिनिधि भी थे। हमने छह चुनाव क्षेत्रों का दौरा किया, चुनाव प्रक्रिया को समझा। दिलचस्प बात यह थी कि पहली बार वहाँ ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा था। इससे पहले, पिछले चुनाव मत-पत्र से होते थे। तख़्तापलट का एक कारण यह है कि अब वहाँ कोई व्यक्तिपरक मूल्यांकन नहीं होता है। लोगों से आपको यही सुनने मिलेगा।

तख़्तापलट की एक वजह यह थी कि एनएलडी (NLD) का आरोप था कि दो चरणों में मतदान हुआ क्योंकि मतपत्र से मतदान कराए गए थे, इस उम्मीद में कि आंग सान सू की कि नेतृत्व वाली एनएलडी को भारी बहुमत मिलेगा और वे 2008 के संविधान में बदलाव कर सकती हैं जिसमें सेना के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। अब, इसकी वजह से, उन्होंने ईवीएम बनाने का फैसला किया। ईवीएम काफी हद तक भारतीय ईवीएम जैसी ही हैं। वे भारतीय ईवीएम से प्रेरित हैं। उन्हें बनाने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। वे देश में ही बनी हैं। मैं ईवीएम समिति से भी मिली और उनसे विस्तार में बात की।

संघ चुनाव अध्यक्ष ने चुनाव और ईवीएम निर्माण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। ईवीएम पर काम करने वाले बहुत, बहुत काबिल लोग थे और उन्होंने मुझे बताया कि प्रक्रिया क्या थी। यह चौथा प्रोटोटाइप है जिसे उन्होंने वास्तव में प्रयोग किया है। यह तो चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया के बारे में कहा जा सकता है लेकिन एक दिलचस्प बात बता दूँ, चुनावों में वास्तव में, जब मैं घूम रही थी और देख रही थी कि वे सूचियां, मतदान सूचियों को किस तरह से देख

पा रहे हैं, तो 75,000 नोटबुक, डिजिटल नोटबुक्स या छोटे आईपैड्स जैसे थे, जो मतदान केंद्रों पर हर एक एजेंट को दिए गए थे, जिनमें सभी मतदाताओं की सूची, पता, मतदान- क्षेत्रवार नाम थे। ये आईपैड्स जैसे उपकरण चीन द्वारा उपलब्ध कराए गए थे और चीन-निर्मित थे।

अब ईओ (Eos) की बात करते हैं, चुनाव के बाद क्या होता है? एक बार फिर, बहुत ज़रूरी सवाल क्योंकि हमने कहा है, चाहे आप उन्हें जातीय सशस्त्र संगठन कहें, आप उन्हें जातीय प्रतिरोध संगठन कहें, आप उन्हें लोकतांत्रिक शक्तियां कहें, हमने उन्हें तख़्तापलट के ठीक बाद राष्ट्रीय एकता सरकार ना की एक अम्ब्रेला एंटीटी के तहत आते देखा। सच तो यह है कि केआईए ने चुनावों में बाधा नहीं डाली, चुनावों को होने दिया। एमएनडीए (MNDA) ने चुनावों में बाधा नहीं डाली। एनएलटी (NLT) और एलए (LA), ये बड़े ईओ हैं, उन्होंने चुनावों में बाधा नहीं डाली। जहाँ उन्हें समस्या हुई और मैं [51:00] उस बात पर वापस आऊँगी जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था, कि लगभग 67, 64 निर्वाचन क्षेत्रों में वे चुनाव नहीं लड़ सके। उनमें से 60% निर्वाचन क्षेत्र भारत के सीमावर्ती हैं।

तो सर, उनमें से करीब 40 निर्वाचन क्षेत्र हमारे सीमा से सटे हैं, क्योंकि वे चिन स्टेट, अराकान स्टेट थे। अराकान स्टेट, उन्होंने शुरू में कहा था कि वे 17 में से करीब 10 पर चुनाव लड़ेंगे। वे मुश्किल से तीन पर ही लड़ने का प्रबंध कर पाए। चिन स्टेट, हम जानते हैं कि चिन समूह बहुत अधिक बंटे हुए हैं। एक दो जगहों को छोड़ दें तो वे चुनाव का प्रबंध वहाँ मुश्किल से कर पाए। तो जिन 64, 67 निर्वाचन क्षेत्रों में वे चुनाव नहीं लड़ पाए, उनमें से 40 भारत के सीमावर्ती थे।

इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें विवाद का समाधान नहीं मिलेगा बल्कि हमें विवाद के साथ समझौता करना होगा। इससे यह भी पता चलता है कि ये ईओ किसी भी दूसरी सीमा के मुकाबले भारत की सीमा पर अधिक सक्रिए होंगे। आपने कहा, सर, कि मेरे मित्र जयंत ने कहा कि जमात ने बांग्लादेश में सीमा जीत लिए हैं। शायद उन सीमाओं पर हमें कोई समस्या है। हमें निश्चित रूप से भारत के सीमावर्ती म्यांमार में समस्या है।

मैं एनयूजी (NUG) और एनयूसीसी (NUCC) के बारे में भी थोड़ी बात करूँगी। एक बार फिर, उन्होंने अपना महत्व खो दिया है क्योंकि शुरू से ही, बड़े ईओ एनयूजी (NUG) का हिस्सा नहीं रहे हैं। अराकान आर्मी, जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, और जो एक बहुत मज़बूत संगठन है, कभी भी एनयूजी (NUG) का हिस्सा नहीं थी। क्या उनका कोई सामान्य राजनीतिक कार्ययोजना है? नहीं, उनके पास कोई सामान्य राजनीतिक कार्ययोजना नहीं है। क्या कोई नेता है, क्या आप किसी नाम के बारे में सोच सकते हैं, जो विपक्ष की बागडोर संभाले? नहीं, आप नहीं सोच सकते। पिछली क्रांतियों के उलट, आपके पास डॉ आन सान सू की थीं, जो विपक्ष का चेहरा, नेता थीं। क्या आपको यहाँ कोई विपक्ष नज़र आता है? क्या आप कोई नाम जानते हैं? नहीं, आप नहीं जानते।

इसलिए, यह बंटवारा उन्हें थोड़ा महंगा पड़ेगा। आप अराकान आर्मी को देखें, क्या उन्होंने यह कहने के लिए कोई विशेष शब्द प्रयोग किया है कि हम किस तरह की बातचीत करना चाहते हैं या नहीं? उन्होंने संघटन शब्द का प्रयोग किया है, उन्हें संघ शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने संगठित शब्द का प्रयोग किया है। आप केआईए (KIA) से पूछिए, केआईए (KIA) कहेगा, हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे। कोई स्पष्ट कार्ययोजना नहीं है। आप चिन समूहों से पूछिए,

सीएनएफ (CNF), जो पहले एक बड़ा अम्ब्रेला समूह था, चिन समूह, उसमें लगभग 16 समूह हैं। आप सीबी (CB) को देखिए, उसमें करीब छह, सात और समूह हैं।

आप किससे समझौता करते हैं? स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, इसमें समस्या होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उत्तरी इलाकों में जहां टीएनएलए (TNLA), एमएनडीए (MNDA), जहाँ यूनाइटेड बार स्टेट है, आप में से कई लोग जिन्होंने म्यांमार के बारे में पढ़ा है, वे इन नामों को जानते होंगे, वहाँ 95% मतदान हुआ। इससे आपको इन सीमाओं पर चीन के प्रभाव का पता चलता है। अब, मुझे सत्र के आरंभ में ही समय-सीमा का ध्यान रखने के लिए बता दिया गया था। मैं समय-सीमा का पूरा ख्याल रखूंगी।

अंतिम बात जिस पर श्रीपति चाहते थे कि मैं थोड़ा और विस्तार से जानकारी दूँ, वह परिणामों, भू- राजनीतिक, भू-रणनीतिक परिणामों के बारे में थी। इसमें एक समस्या है। और मुझे लगता है कि हम इस बारे में जितनी अधिक बात करेंगे, जितनी अधिक चर्चा करेंगे, तभी हम समस्या की गंभीरता को समझ पाएंगे। म्यांमार को केवल इस आसान तरीके से नहीं देखा जा सकता कि किसके पास अधिक प्रदेश है, तत्माडॉ या ईओ के पास। और भी बहुत कुछ चल रहा है। यह मेथम्फेटामाइन उत्पादन का केंद्र बन गया है।

जब से अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती पर प्रतिबंध लगा है, उन्होंने म्यांमार में एक तैयार आपूर्ति श्रृंखला मिल गई है। यूएनओडीसी (UNODC) ने म्यांमार को सिंथेटिक ड्रग उत्पादन का केंद्र कहा है। यदि आप केवल 10% भी लेते हैं, जो यूएनओडीसी (UNODC) आमतौर पर करता है, तो इसका अनुमानित मूल्य 40 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह तो केवल पकड़ा गया है। हम मेथम्फेटामाइन की अलग- अलग प्रजातियों पर भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमने शुरू में या बा पिल्स के बारे में सुना था, जो 70 के दशक से मौजूद है।

लेकिन अब, वे बहुत तेज़ी से प्रसंस्करण कर रहे हैं। वे प्रयोग कर रहे हैं। ये कोई छोटी प्रयोगशाला नहीं है। ये इसके लिए बनी परिष्कृत, उच्च- तकनीक वाली प्रयोगशालाएं हैं, जिन्हें चीन के सिंडिकेट चला रहे हैं। मैं अक्सर यह संख्या बताती हूँ क्योंकि मुझे यह संख्या हैरान करती है, सर, 2024 में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में, हमने, भारतीय तटरक्ष बल ने, लगभग 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के मेथम्फेटामाइन पकड़ी थी, मेरा अनुमान है कि लगभग 60,000 गोलियां, 3,000 किलो थीं। यह अच्छी बात नहीं है।

किसी भी रूप में, मुझे लगता है कि हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। भारत में आने- जाने के बड़े इलाके- मिज़ोरम सीमा से होकर चम्फाई ज़िला, वहाँ से वितरित, मणिपुर से मोरेह तामू, नागालैंड इसका परिणाम- नशीले पदार्थों की तस्करी। इसका प्रभाव सुरक्षा पर भी पड़ता है? नहीं, इसका प्रभाव विकास पर पड़ता है और स्वास्थ्य पर भी। यही वजह है कि मिज़ोरम में देश में एचआईवी की दर सबसे अधिक है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5% अधिक है। मणिपुर दूसरे और नागालैंड तीसरे स्थान पर है।

वहाँ और क्या हो रहा है? एक बार फिर, मैं आपको बस एक छोटी सी जानकारी दे रही हूँ। साइबर स्कैम। साइबर स्कैन से पिछले वर्ष हमें 22,500 करोड़ रु. का राजस्व घाटा हुआ। यह तो रिपोर्ट किया गया आंकड़ा है सर। बहुतेरे

साइबर अपराधों की रिपोर्ट ही नहीं होती। इन जगहों पर जाकर और मेसा में, सीमा के पार, साइबर उद्योग में काम करने वालों का इंटरव्यू लेने के बाद, मैं आपको बता सकती हूँ कि साइबर स्कैम उद्योग में जाने वाले बहुत से लोग भारतीय हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी बोल लेते हैं और इनमें से बहुत सारे स्कैम अंग्रेजी भाषा में होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वे सभी बेकसूर नहीं हैं। उनमें से बहुत से लोग वहां जाने का फैसला कर रहे हैं। जिन तीन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, उनमें से एक को पता था कि वह क्यों जा रहा है।

दूसरी बात, हमारे लिए वित्तीय समस्या होने के अलावा, सच तो यह है कि, साइबर स्कैम चीनी सिंडिकेट ही चलाते हैं। यह पैसा चीनी सिंडिकेट को जा रहा है। और जिन एनजीओ से मैं मिली, उनके हिसाब से, यह विश्व इतिहास में गुलामी के बाद का सबसे बड़ी मानव तस्करी की घटना मानी जाती है जिसमें किसी भी समय, इन साइबर स्कैम कंपाउंड में 200,000 लोग होते हैं। इन कंपाउंड्स में वह सब कुछ है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उनके पास सुपरमार्केट हैं, उनके पास डिस्कोथेक हैं, उनके पास पब हैं, उनके पास एचआर हैं, उनके पास प्रशिक्षण केंद्र हैं।

यदि आप विफल हो जाते हैं तो अंगों का व्यापार किया जा सकता है। भारत ने देश- प्रत्यावर्तन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। वास्तव में दुख की बात यह है कि कुछ छोटे देश, शायद अफ़्रीका से, शायद दूसरे देशों से, उनके कैदी वहीं रह जाते हैं। उन्हें देश में वापस बुलाने वाला कोई नहीं होता। तीसरी बात यह है कि क्या होता है। दुर्लभ खनिज। एक बार फिर, केवल दो मिनट का समय दें। यह बहुत महत्वुपूर्ण बिन्दु है। दुर्लभ खनिज। हमने इस पर बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमने इस पर बात करना चीन के इस मुद्दे पर बात करना शुरू करने के 15 साल के बाद शुरू किया है।

चीन- अमेरिका टैरिफ जंग में वास्तव में स्थिति को बदल दिया है। जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया तो चीन ने सबसे पहले कहा, हम तुम्हें कोई भी अनिवार्य दुर्लभ खनिज नहीं बेच सकते। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अमेरिका ने तत्माडॉ से प्रतिबंध हटा लिया? क्योंकि तत्माडॉ, सेना, सैन्य जुंटा पर अमेरिका का नज़रिया हमेशा बहुत स्पष्ट रहा है।

लेकिन उन्होंने प्रतिबंध हटा दिए। उन्होंने न केवल प्रतिबंध हटाए, बल्कि विश्वसनीय रिपोर्टें भी आईं। ये रिपोर्ट्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और आप भी उन्हें पढ़ सकते हैं, जिनमें कहा गया था कि वे म्यांमार में दुर्लभ खनिज तक पहुँचने के लिए केआईए और दूसरे समूहों के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। समस्या, स्पष्ट है, यह है कि चीन के पास प्रसंस्करण इकाईयां हैं, वह म्यांमार से दुर्लभ खनिज और भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा खरीददार है। 90% प्रसंस्करण चीन में होता है। विश्व भर में इसका 90% चीन से आता है।

जब तक शेष विश्व इसे समझेगा, मुझे लगता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी होगी। भारत के लिए भी यह समस्या वाली बात होगी, क्योंकि हम पर बहुत अधिक विदेशी दखलंदाज़ी बड़ी समस्या होने वाली है। बहुत से दूसरे देश सौदा करने, प्रवेश पाने को उत्सुक होंगे। नशीले पदार्थ आज भी जातीय सशस्त्र संगठनों को जिंदा रखेंगे। मैं ईओ को बहुत करीब से देख रही हूँ, उनके पास पहले किस प्रकार के हथियार थे, उनके पास किस तरह की व्यवस्था थी। दो साल में वे कहीं अधिक आधुनिक हो गए हैं।

देवियों और सज्जनों, जब मैं कहती हूँ कि वे ड्रोन के पुर्जे खरीद रहे थे, तो आज, वे सीधे सबसे उन्नत ड्रोन खरीद रहे हैं। वे एंटी- ड्रोन सिस्टम भी खरीद रहे हैं। इसलिए उनके पास इनमें से कुछ भी खरीदने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मैं इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि, मुझे लगता है कि मेरे 10 मिनट की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। मैं इस बात के साथ अपनी बात खत्म करूँगी कि हमें नहीं मालूम कि म्यांमार में राजनीतिक स्तर पर क्या होने वाला है। जैसा कि हमने इस बारे में बहुत बात की है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक कानून बनाया है, जिसे, क्या कहते हैं? उन्होंने एक परिषद बनाई है, सलाहकार परिषद।

सलाहकार परिषद के पास काफी शक्ति है। क्योंकि पहले बहस यह थी कि राष्ट्रपति लिंग क्या करने वाले हैं? क्या वह फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? वे संसद और सशस्त्र सेनाओं को कैसे नियंत्रित करेंगे? अब, इस परिषद के बारे में हम अधिक नहीं जानते लेकिन हम यह जानते हैं कि इसके पास काफी शक्ति होगी जो कानूनी शासन को प्रभावित कर सकती है, जो विदेशी संबंधों को प्रभावित कर सकती है और जो कुछ दूसरी बातों पर प्रभाव डाल सकती हैं। यह कार्यकारी शक्तियां और न्यायिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती।

लेकिन, प्रभाव में, इसके पास राष्ट्रपति से अधिक शक्ति हैं, और अधिकार में, थोड़ी कम। राष्ट्रपति लिंग कार्यकारी राष्ट्रपति हों, लेकिन वे राष्ट्रपति बनें या न बनें, किसी-न-किसी तरह, मेरे विचार से, वे सरकार और सशस्त्र सेनाओं, दोनों पर अधिकार बनाए रखेंगे। भारत इससे कैसे निपटता है, यह तो भारत पर ही निर्भर करता है। हमने कठिन संतुलन बनाए रख कर अच्छा काम किया है। हमने संवाद के माध्यम खुले रखे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या हमारी सीमा पर हमारी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, भविष्य के बारे में हमारी भू-राजनीतिक, भू- रणनीतिक, व्यावहारिक विचार जो हमारे पास होनी चाहिए। आखिर में, यह विवाद उचित है, हमें इसके साथ समझौता करना होगा। चुनाव कोई हल नहीं है। धन्यवाद।

सब्यसाची दत्ता: आईसीडब्ल्यूए और श्रीपति एवं अन्वेषा को आज के आमंत्रण के लिए बहुत- बहुत धन्यवाद। मैं आज के सत्र का अंतिम वक्ता हूँ। मुझे पता है कि हम निर्धारित समय से 20 मिनट अधिक ले चुके हैं। मुझसे पहले मेरी मित्र रामी ने म्यांमार के मुद्दों पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। लेकिन मैं सबसे पहले एशियन कॉन्फ्लुएंस, जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, उत्तरपूर्वी भारत का एक विचार मंच है और हमारे देश की सीमाएं बांग्लादेश एवं म्यांमार से लगती हैं। बंगाल की खाड़ी से कनेक्टिविटी में भारत के हितों के लिए यह बहुत आवश्यक है।

ये दोनों देशों, चाहे बांग्लादेश के माध्यम से हो या म्यांमार के जरिए, उत्तरपूर्व का निर्माण करते हैं, उसे ज़मीन से घिरे होने पर राहत पहुँचाते हैं। इसलिए, उस नज़रिए से देखने पर, पहली चीज़ जो मुझे नज़र आती है, वह यह है कि यदि हम सीमा के पार देखें, तो म्यांमार में हमारे पास बहुत बड़ा मानवीय संकट है। एक बड़ी आबादी नाराज़ है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। रामी ने अपराध के नज़रिए, नशीले पदार्थों के नज़रिए, विवादों के बारे में बात की है। इसलिए जब हम सुरक्षा पर नज़र डालते हैं, अर्थव्यवस्था को देखते हैं, हमें यह देखना होगा कि हम ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ आबादी बहुत अधिक वंचित और विवश है। मानवीय मदद मिलने के नज़रिए से बहुत कमज़ोर है, चाहे आपदा आ जाए या महामारी या कुछ और।

उस नज़रिए से, यदि मैं चुनावों को देखूँ तो मुझे कई बार म्यांमार जाने का मौका मिला है। एक बार, जनरल ने खुद एक तथाकथित शांति सम्मेलन में हमारा स्वागत किया था, जिसमें इस बारे में बात हुई कि वह देश में किस तरह शांति लाना चाहते हैं। लेकिन यह क्या, और काफी लोगों से बात करने के बाद, उम्मीद की किरणें नज़र आईं कि चुनाव कुछ नया, कुछ अलग करने का मौका हो सकता है। चुनावों के बाद, हम पाते हैं कि चुनावों को एक प्रकार की पावर इंजीनियरिंग एक्सरसाइज़ के तौर पर देखा जा रहा है। और इससे जनरल को, विशेषरूप से संघीय विधायी परिषद के बनने से, बहुत अधिक अधिकार मिल जाएगा।

तो इससे उन्हें इस बात पर बहुत छूट मिल जाती है कि भविष्य में क्या होने वाला है, एक व्यक्ति के रूप में उनके लिए। दूसरी बात यह है कि हम बड़ी संख्या में मतदान देखते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग जिन्हें यूएसडीपी (USDP) ने वोट दिया है। यूएसडीपी (USDP), अपनी बड़ी संख्या के साथ और जनरल एवं यूएसडीपी के बीच के संबंध कैसे हैं। सेना और राजनीतिक दल जो करने जा रहे हैं, वह एक दिलचस्प नज़रिया होगा, मुझे लगता है कि इस पर नज़र बनाए रखनी होगी। इससे मौके मिल सकते हैं और मुझे लगता है कि यह उम्मीद की एक किरण है।

चुनावों के बाद जनरल की तरफ से कुछ पहल किए गए। आने सुना होगा कि पूर्व वरिष्ठ मंत्रियों में से एक टुन टुन नौंग को को गिरफ्तार किया गया था और उन पर इन सिंडिकेट में अपराध के खिलाफ आरोप थे आदि, आदि। तो यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अच्छा शासन और इस तरह की बातें ऐसे तरीके हैं जिनसे जनरल, वे यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने बात करने की पहल की है, जो राष्ट्रीय युद्धविराम समझौते का हिस्सा हैं। तो वे पहल हो रही है। ये प्रतीकात्मक हैं या असल में ऐसा हो रहा है, यह देखना अभी बाकी है।

कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि सेना एक ऐसे समय की ओर बढ़ रही है, जहाँ सैन्य पूर्वाग्रह के साथ, वह दूसरे खिलाड़ों के साथ विवादों को देखेगी। और मैं आपसे दूसरे खिलाड़ियों के बारे में भी बात करूंगा। मैंने उन्हें दो हिस्सों में बांटा है। लेकिन हम बहुत अधिक हवाई बमबारी देखते हैं और विशेषरूप से उनके पास जो नए ड्रोन आए हैं, उनसे बमबारी किया जाना पाते हैं। यह बात सेना के लोगों के खिलाफ होने और मानवीय संकट को और अधिक बढ़ाने के तौर पर सामने आई है। जो भी गुरिल्ला युद्ध हो रहा है, जो कुछ भी ऐसा हो रहा है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सेना की कार्पेट बॉम्बिंग (व्यापक क्षेत्र पर बमबारी) लोगों को पसंद नहीं आई है। इसलिए यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि सरकार देश के लोगों के लिए है, तो यह सच में बहुत अच्छा स्थित में नहीं है।

दूसरी बात है, बामर हार्टलैंड। जब मैं बामर हार्टलैंड, अंयार कहता हूँ, जो मांडले, बागो, सागाइंग, यांगून है, वह पूरी पट्टी, ने पी ताव, वह वाली पट्टी, हम एक प्रकार का विद्रोह देखते हैं जहाँ एनयूजी को यदि अपना महत्व बनाए रखना है तो उन्हें सक्रिए रहना होगा। वे बहुत अस्थिर रहे हैं। लेकिन फिर हम एसआरए (SRA), स्प्रिंग रेवोल्यूशन आर्मी जैसी चीजों को बढ़ते हुए देखते हैं। हम कई पीडीएफ का एक साथ होना देखते हैं। हम एनयूजी संरेखित पीडीएफ को अपना काम करते हुए देखते हैं।

तो हम देख रहे हैं कि सेना के मुकाबले हार्टलैंड में कई प्रकार के अलग- अलग विवाद हो रहे हैं। सेना इससे कैसे निपटेगी, यह हमें देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से, हार्टलैंड में प्रबंधित विवाद और उथल- पुथल का दौर होने का अंदाज़ा है। यदि आप बाहरी इलाके में जाएं जो म्यांमार का दूसरा हिस्सा है, जो जातीय हथियारबंद समूह हैं, जैसा कि मुझसे पहले विचारों को साझा कर रही वक्ता ने बताया, इनमें से ज्यादातर इलाके सेना के नियंत्रण में नहीं हैं। हाँ, काचिन, यदि मैं चारों ओर से देखूँ, तो कैरन्स, काचिन्स, चीनियों की बहुत बड़ी भूमिका है। दुर्लभ खनिज, भू-राजनीतिक हितों जैसे कारक की बहुत बड़ी भूमिका है।

यह भी याद रखें कि वे बहुत समय से हैं, खासकर काचिन, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, जो बहुत संस्थागत हैं। चिन बहुत, बहुत अधिक बंटे हुए हैं लेकिन इस पूरे परिदृश्य में जो दिलचस्प बात है वह है अराकान आर्मी। मुझे लगता है कि वे एक ऐसी शक्ति के रूप में सामने आए हैं जिनसे निपटना होगा। सबसे पहले, उनकी बहुत सारे प्रदेशों पर उनका अच्छा नियंत्रण है। वे चिन के एक हिस्से का साथ साझा भी कर रहे हैं, जहाँ चिन ब्रदरहुड के माध्यम से पलेतवा जैसे शहरों में बहुत प्रभाव डाल रहे हैं, यह हमारे मिज़ोरम के ठीक दक्षिण में है। उनका चिन लोगों के साथ गठबंधन है।

इसलिए वे एक तरह के बल कारक के रूप में उभर रहे हैं, जिसमें सेना को दूसरे जातीय हथियारबंद संगठनों की बजाय, अराकान आर्मी से एक अलग स्तर पर निपटना होगा। इसलिए मेरा यहाँ कहना है कि हमें इस समस्या का विश्लेषण करने की बहुत ज़रूरत है। यह एक जैसा नहीं है, जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अराकान बांग्लादेश की सीमा से भी लगा हुआ है। रोहिंग्या संकट कैसे सामने आएगा, हमने अभी सुना है कि प्रोफेसर श्री खलीलुर रहमान अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं या जैसा मैंने सुना है, उनके विदेश मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। संभव है कि मैं गलत होऊँ।

लेकिन याद रखें कि एक वही थे जो इस प्रदेश से रोहिंग्या के माध्यम से मानवीय गलियारे को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो अराकान और बांग्लादेशी, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स और बांग्लादेश के चटगांव इलाके के बीच काम करेंगे। निश्चित रूप से दोनों ही हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों के बिल्कुल किनारों पर हैं, विशेषरूप से मणिपुर और मिज़ोरम राज्यों की सीमा से सटे हुए हैं।

तो यह अलग- अलग कारक, आकर्षण और प्रेरक (पुल एंड पुश) कारकों को उत्तरपूर्व के नज़रिए से देखने का एक बहुत ही जटिल जाल होने वाला है। राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मिज़ोरम सरकार, मणिपुर की नई सरकार इन सबसे कैसे निपटती है? केंद्र और राज्य इन सब पर राजनीतिक रूप से कैसे एक साथ आते हैं? और हम एक बड़ी समस्या या एक बड़ा समाधान कैसे निकालते हैं? छोटी- छोटी, सूक्ष्म स्तर की प्रणालीगत समस्याओं के इस जटिल जाल में, जो मौजूद हैं, है ना? भारत के पछीत में।

मुझे लगता है, क्योंकि समय की कमी है, मुझे लगता है कि चुनाव के बाद, सेना प्रयोग करेगी, आप जानते हैं, ऐसी शर्तें रखी जाएंगी ताकि सच में सौदा किया जा सके। चाहे वह बमबारी हो, चाहे संवाद हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसके पास ज्यादा मोलभाव करने की शक्ति है या इलाके पर कब्ज़ा है, किसके पास मोलभाव करने

की शक्ति अधिक है। मेरी अंतिम बात, समय बचाते हुए, यह होगी कि जहाँ तक भारत का सवाल है, मुझे लगता है कि हमारी सुरक्षा, निश्चित रूप से चिंता का गंभीर विषय है।

लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चिंता या उस चिंता का प्रवेश बिन्दु, लोग होने चाहिए। क्योंकि आखिर में, यदि देश में लोग सत्ता के खेल और भू- राजनीति में उलझ जाते हैं तो यह लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। मैं यह भी कहूँगा कि चीन ने बहुत कुछ खो दिया है। क्योंकि चीन में रोज़गार नहीं है। म्यांमार के लोग चीन के साथ समझौता कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चीन के साथ सौदा करना है। लेकिन चीन के साथ विश्वास का कारक बहुत नीचले स्तर पर है। इसी तरह, सेना पर भी लोगों का भरोसा बहुत कम है।

यहाँ, मुझे लगता है कि भारत को, यदि मैं कह सकता हूँ तो ज्यादा लोगों पर ध्यान देने वाली कहानियों और तरीकों को अपनाना चाहिए, यह देखना चाहिए कि ज़मीन पर लोगों की मदद कैसे की जा सकती है, चाहे वे कहीं भी हों, ताकि चीज़ें आगे कैसे बढ़ें, इस पर अधिक सकारात्मक असर पड़े। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की भूमिका, बांग्लादेश की नई सरकार, राज्य सरकारों की भूमिका, एसएसी को शामिल करने की भूमिका, तथाकथित नॉन- स्टेट लेकिन इस मामले में स्टेट एक्टर्स जैसे अराकान आर्मी, को शामिल करने की भूमिका, यह बहुत सारे हितधारकों का एक समूह है जो बहुत छोटे से इलाके में एकजुट हो रहे हैं।

हम उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, यह देखना अभी बाकी है। यह एक ऐसा बिन्दु होगा जहाँ वरिष्ठ जनरल, सुरंग की दूसरी छोर पर रोशनी दिखे, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यदि किसी सुबह वह उठें और कहें कि हम लड़ाई लड़ते-लड़ते थक चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे सबको साथ बुलाकर एक- दूसरे से बातचीत करवानी चाहिए।

मेरी जनता परेशान हैं। मेरे लोग परेशान हैं या हमारे लोग दुखी हैं। यदि ऐसा होता है तो यही एकमात्र तरीका लगता है। बेशक, यह मैं एक इंसान के रूप में बात कर रहा हूँ लेकिन इसके अलावा, मुझे यह भी लगता है कि हम कम-से- कम अल्प से मध्यम अवधि में, संस्थागत तौर पर बंटवारे, लंबे समय तक चलने वाले विवादों का समय देख रहे हैं और निश्चित रूप से दीर्घकाल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह किसी को नहीं पता। बहुत- बहुत धन्यवाद।

प्रीत मलिक: क्या यह काम कर रहा है? खैर, जहाँ तक समय की बात है, हमने हर मुमकिन सीमा पार कर ली है। जल्दी से, मैं प्रश्नोत्तर सत्र आरंभ करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि आप अपना सवाल पूछें, क्या मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ? किसी ने भी हर बात के पीछे चुप्पी साधे देश की बात नहीं की और देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है। शायद आप हमें बता सकें कि इस पर आपका क्या विचार है।

श्रीराधा दत्ता: धन्यवाद। मैंने खलील रहमान का उल्लेख इसलिए ही किया था। असल में वे अमेरिका के प्रतिनिधि हैं जो अभी कैबिनेट में हैं। मुझे लगता है कि वह पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। तो हाँ, निश्चित रूप से जुलाई के विद्रोह के दौरान और उसके बाद भी अमेरिका के प्रभाव के बारे में सुना है। हमने भी सालों में ऐसा देखा है और यह पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने हमेशा कहा है कि जमात को राजनीतिक साझीदार क्यों नहीं बनाया

जाए? कुछ लोगों का कहना है कि जमात को अमेरिका मुख्यधारा में शामिल कर रहा है लेकिन असल में अमेरिका बीते 50 वर्षों से जमात को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए काम कर रहा है। यह कोई नई बात नहीं है।

मुझे लगता है कि इस समय और शायद यही एकमात्र मौका था, हम दोनों ने स्थिति को ठीक से समझाया था, कि पहली बार हमने जमात को मुख्यधारा बनते देखा है। अमेरिका के साथ उसेक संबंध बहुत स्पष्ट हैं। बात यह है कि एनएसए (NSA), जो सांसद नहीं थे, बाकी सभी मंत्रियों ने किसी-न-किसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो थोड़ा असर तो है।

हमने अंतरिम गवर्नर को भी देखा है। चुनाव से ठीक तीन दिन पहले, शायद चार दिन पहले, उन्होंने अमेरिका के साथ एक समझौता किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा टैरिफ लाइन को 50 और 30 से कम कर के 19 कर दिया गया है। इसके अलावा, इसका एक बड़ा रक्षा सेना पक्ष भी है जिसमें कई व्यापार मुद्दे शामिल हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप व्यापार समझौते के पहले कुछ पन्नों को देखें तो बांग्लादेश करेगा, बांग्लादेश करेगा, बांग्लादेश करेगा (Bangladesh will, Bangladesh will, Bangladesh will) लिखा मिलेगा।

अगले पन्ने पर, अमेरिका संभवतः, अमेरिका संभवतः (US may, US may) लेकिन फिर से बांग्लादेश करेगा (Bangladesh will) लिखा मिलता है। स्पष्ट है, इस सरकार के लिए इससे पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ, हम बांग्लादेश में यूके की राजदूत से भी कई बार मिल चुके हैं और उन्होंने भी, मैंने अकसर इस बारे में बात की है कि बीते 18 महीनों में, एक विशेष बाहरी शक्ति, जिसे हम हमेशा नॉन-रेज़िडेंट साउथ एशियन शक्ति कहते हैं, जो चीन है, ने, बांग्लादेश में कहीं अधिक अतिक्रमण किया है।

अब, चीन सच में वहाँ अपनी उपस्थिति बनाए रहा है। चीन शेख हसीना, खालिदा ज़िया, सबके लिए, इस अंतरिम समय के लिए भी, एक हमेशा बने रहने वाला साझीदार रहा है। मुझे लगता है कि, लेकिन मैं वास्तव में यहीं पर अपनी बात समाप्त करूँगा, यह कहते हुए कि अमेरिका वास्तव में हमारे लिए एक अच्छा साझीदार होगा क्योंकि कई मामलों में, हम एक ही स्थिति में हैं, लोकतंत्र उनमें से एक है। लेकिन परंपराओं, मूल्यों, नियमों के मामले में हम अलग हैं।

मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत कई मुद्दों पर एक जैसे हैं, जबकि हमारे लिए चीन, निश्चित रूप से, इस तत्थ के बावजूद कि चीन ने बांग्लादेश के साथ इतने करीब से काम किया है, असल में, वही अकेला है जिसने उन्हें बुनियादी ढांचा और चीन में काम करने वाली हर एक स्थिति के लिए समर्थन दिया है। लेकिन उन्हें कभी भी ऋण अनुपात संबंधी समस्या नहीं हुई है। इसलिए बांग्लादेश भी इस बारे में बहुत सतर्क रहा है। मुझे लगता है कि हमें न केवल अमेरिका पर नज़र रखनी होगी बल्कि हमें चीन पर भी बहुत करीब से नज़र रखनी होगी। ये दोनों ही भारत के लिए कारक होंगे।

प्रीत मलिक: अच्छी बात है। धन्यवाद। दर्शकों अब आप सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ बैठे व्यक्ति, जी, कृपया अपना नाम बताएं और जिनसे अपने सवाल का जवाब चाहते हैं, उनको संबोधित करते हुए सवाल पूछें।

सुबोध सी भारती: अध्यक्ष महोदय, बहुत- बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय वैश्विक परिषद में शोध सहयोगी हूँ। मेरा सवाल का जवाब बांग्लादेश पर बोलने वाले पैनल के कोई भी सदस्य दे सकते हैं। मैं केवल यह जानना चाहता था कि जमात और एनसीपी के विपक्ष के बैठने के संदर्भ में और बांग्लादेश में बदले की राजनीति के इतिहास और निश्चित रूप से राजनीतिक नियुक्तियों को देखते हुए बांग्लादेश की राजनीति की दिशा क्या होगी। और हाँ, जमात नेतृत्व ने तारिक रहमान से बैठक की और उसके बारे में ट्वीट किया और कहा कि वे एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में सहयोग करेंगे। बदले की राजनीति से बचने का भी अनुरोध किया गया है। इसी तरह, एनसीपी के नेताओं ने भी तारिक रहमान से बैठक की और वही बात हुई। धन्यवाद।

जयंत राय चौधरी: जी हाँ। ठीक है, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि दो मूल शाखाएं हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं। एक है बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति और दूसरी है बाहरी राजनीति। मैं पहले बाहरी राजनीति पर बात करती हूँ। स्पष्ट है, यदि आप रीसेट शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो उन्हें भारत के साथ अपने संबंधों को रीसेट करना होगा। लेकिन यह धीरे- धीरे होना चाहिए। वे किसी भी ऐसी चीज़ में जल्दबाज़ी नहीं करना चाहेंगे जहाँ विपक्ष उन्हें भारत का समर्थक कहे, जो शेख हसीना के लिए समस्या थी। भारत को भी सावधानी से चलना होगा, क्योंकि वह चाहेगा कि संबंध बिना किसी भी प्रकार से बदनाम हुए बेहतर हों।

हमारे संबंधों में धीरे- धीरे सुधार होगा और मुझे लगता है कि तारिक रहमान का भी यही इरादा होगा। वह भारत को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहेंगे। जैसा कि यूनुस ने किया, वह जो चाहे कहें, लेकिन सच तो यह है कि उनके कार्यकाल में हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जहाँ तक घरेलू राजनीति की बात है, मैंने कहा था, और मुझे लगता है कि श्रीराधा भी सहमत होंगी, कि जमात सड़कों और संसद दोनों जगह ताकतवर होती जाएगी, इसले बीएनपी को उसी हिसाब से अपने कामों का ध्यान रखना होगा। अवामी लीग को किस तरह से इजाज़त दी जाएगी या नहीं, इसका फ़ैसला भी इन दोनों पार्टियों द्वारा और सड़कों पर ही किया जाएगा क्योंकि अवामी लीग खुद को बदलती भी है, ऐसा लग रहा है कि वह खुद को बदलेगी, तो हमें उस पर नज़र रखनी होगी।

अज्ञात प्रतिभागी: [प्रश्न पूछने के दौरान आवाज सुनाई नहीं दी] अब सवाल यह है कि, क्योंकि दोनों देशों में घरेलू राजनीति और विदेश नीति एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मुझे लगता है कि दोनों सरकारों पर बहुत दबाव होगा और बांग्लादेश एवं म्यांमार दोने के पिछले इतिहास को देखते हुए, आने वाले कम- से- कम एक वर्ष में यह बहुत अस्थिर रहने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि यही बात है। मैं केवल टिप्पणी कर रहा हूँ, कोई सवाल नहीं पूछ रहा।

प्रीत मलिक: कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया पूछिए। इसके बाद मैं केवल एक, दो या तीन सवाल और लूंगा। चलिए तीनों सवाल एक साथ ले लेते हैं।

आशुतोष रथ: नमस्कार। इतने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए अध्यक्ष महोदय और पैनल के सदस्यों को धन्यवाद। मैं आशुतोष रथ हूँ। परिषद में शोध इंटर्न भी हूँ। मेरा सवाल म्यांमार के बारे में है। पैनल के दोनों सदस्यों से मुझे यह पूछना है कि क्या आपको लगता है कि यूएसडीपी (USDP) के नेतृत्व वाली नई सरकार, जिसे सेना का

समर्थन है, म्यांमार में अलग- अलग ईएओ के बीच उचित शांति प्रक्रिया आरंभ कर सकती है, यह देखते हुए कि विश्व भर में चुनावों को दिखावा या मज़ाक कहा जा रहा है? हालांकि, सभी देशों ने नहीं लेकिन कुछ देशों ने चुनावों का समर्थन किया है लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन के समर्थन को देखते हुए, यह क्षेत्रीय विकास, आंतरिक राजनीतिक के साथ- साथ विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है?

प्रीत मलिका: कृपया अपना सवाल पूछिए।

ज़ीशान अली: नमस्कार। धन्यवाद। मेरा नाम ज़ीशान अली है और मैं परिषद में शोध इंटर्न हूँ। मेरा सवाल विशेष रूप से म्यांमार में हो रहे इन साइबर अपराधों से जुड़ा है। इनमें से बहुत से स्कैम चीन के समर्थन से होते हैं और हमारे बहुत से युवा जो वहाँ जाते हैं, वे तकनीकी रूप से उच्च आईटी कुशलता वाले पेशेवर होते हैं जिन्हें अधिक वेतन वाली नौकरियों का लालच दिया जाता है। वे थाईलैंड जाते हैं और फिर उन्हें अवैध रूप से म्यांमार भेज दिया जाता है। तो क्या इन मुद्दों पर चीन के साथ और बातचीत की ज़रूरत है? क्योंकि ये सबसे अच्छे टैलेंट हैं जो नौकरी की तलाश में थाईलैंड जा रहे हैं लेकिन उन्हें मानव तस्करी एवं दूसरे प्रकार की तस्करियों में फंसाया जा रहा है या यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं? धन्यवाद।

प्रीत मलिक: एक और सवाल। कोई पूछना चाहता है? जी हाँ, पूछिए।

मोहम्मद हादी रज़ा: आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद हादी रज़ा है। मेरा सवाल है कि- 2001 और 2006 के दौरान जब बीएनपी और जमात का गठबंधन था तो हमने भारत के विद्रोही समूहों की संख्या को बढ़ते देखा। मैं यह पूछना चाहूँगा कि भारत को किस तरह के प्रभाव झेलने पड़ेंगे, विशेष रूप से यह कि अब हमारे पास तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर उत्तरपूर्वी प्रदेश हैं? इस सवाल का जवाब पैनल के कोई भी सदस्य दे सकते हैं। धन्यवाद।

प्रीत मलिक: अच्छी बात है। क्या आप जवाब देना चाहेंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जाने का समय हो रहा है।

श्रीराधा दत्ता: जी हाँ। बीते कुछ महीनों में हमने बांग्लादेश के सभी राजनेताओं से, जो चुनाव लड़ रहे हैं, कई बयान सुने हैं। सभी ने किसी-न-किसी तरह यही कहा कि वे भारत के साथ अच्छे, सकारात्मक, रचनात्मक संबंध चाहते हैं। मैंने एक विशेष साक्षात्कार का उल्लेख किया था जो बीएनपी के संयुक्त सचिव ने दिया था- उन्होंने कहा था कि हमें इन चीजों पर फिर से सोचने का कोई तुक नज़र नहीं आता। हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिनसे दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा हो।

तो मूल रूप से, उन्होंने जो बताया है, वह यह है कि वे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और निश्चित रूप से, भारत की चिंताएं और डर बने हुए हैं। यह बात कि संयुक्त सचिव ने इस बात का ज़िक्र किया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे जमाती हैं लेकिन यह भी सच है कि सीमा पर हमेशा अतिवादी स्थिति बनी रहती है। यह बात तब भी सच है जब

आप हमारे बंगाल, मुर्शिदाबाद जाएंगे, तो आपको ऐसी ही स्थिति नज़र आएगी। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार के तत्वों का होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, यह चिंता की बात होगी, मुझे यह भी लगता है कि आज की दुनिया में, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए असल में पड़ोस पर निर्भर रहना बंद करना होगा। भारत को इसका ध्यान खुद ही रखना होगा।

अब हमारे पास तकनीक का भी समर्थन है। हम बहुत कुछ कर सकेत हैं लेकिन अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमें उम्मीद है कि बीएनपी अपनी बात पर चलेगी। प्रधानमंत्री ने अब तक हर एक इंटरव्यू में, जहाँ भी उनसे पूछा गया, कहा है कि वह अच्छे, सकारात्मक संबंध बनाना चाहते हैं। वह स्पष्ट रूप से यह जानते हैं कि 2001 और 2006 में जो हुआ, उससे आज का भारत अलग भारत है। वह जानते हैं कि यह बात हर जगह बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उम्मीद है कि इस बार एक अलग बीएनपी सरकार होगी।

सब्यसाची दत्ता: शांति प्रक्रिया वाले सवाल का बहुत ही संक्षेप में उत्तर। आपने यह सवाल पूछा था, है ना। वास्तव में सेना पर, सीनियर जनरल पर निर्भर करता है लेकिन यदि वे चाहें तो ज़रूर। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें यह ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि विश्वास कैसे बनाया जाए, या कम- से- कम बातचीत का माहौल कैसे तैयार किया जाए, जो अब तक नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसका मूल कारण यह है कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लगातार हो रहे बम धमाकों ने ऐसा माहौल बना दिया है, जहाँ बातचीत करना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए यह उन पर निर्भर करता है।

रामी निरंजन देसाई: मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगी। मुझे खुशी है कि आपने शांति प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछा। मैं सब्या की बात से इतर कुछ कहूँगी। सब्या ने इसे पूरी तरह से ध्यान में रखा है। मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारी ईओ पर भी है। ईओ पर ज़िम्मेदारी इसलिए है क्योंकि यह परंपरागत प्रदेशों के लिए जातीयता होगी? क्या चिन लोग गैर- चिन लोगों को वहाँ रहने देंगे? क्या अराकान रोहिंग्याओं को वापस आने देंगे? क्या काचिन पर काचिन का दबदबा बना रहेगा? ऐसा होना भी चाहिए, वहाँ से ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें ऐसे लोगों को नियुक्त करना होगा जो बात कर सकें।

अब, यदि चिन के पास 30 से अधिक समूह हैं तो आप किससे बात करेंगे? फ़ैसला कौन करेगा? यदि आप सीएनएफ (CNF) के पास जाते हैं तो सीएनएफ (CNF) कहता है कि हमें लगता है कि सीबी (CB) ने हमें धोखा दिया क्योंकि उन्होंने अराकान के साथ साझेदारी की और उन्हें पलेतवा पर कब्ज़ा करने दिया, जो चिन का एक राज्य है। क्या अराकान चिन राज्य में और भीतर जाएगा? क्या वहाँ भी वैसी ही जंग होगी? मुझे लगता है कि यह दो तरफा होगा। एनएसपीएनसी (NSPNC) नाम की एक संस्था है, जो उन जातीय हथियारबंद संगठनों के लिए संवाद करने वाली संस्था है जो इसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने लोगों को संघवाद पर बात करने के लिए बुलाया है। उनमें से एक में सब्या और मैं भी थे। अपनी सीमित क्षमता में, और पूरी विनम्रता के साथ मैं यह कह रही हूँ कि संघवाद को सही मायने में समझने के लिए उन्हें बहुत अधिक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। उनके लिए यह एक अनजान अवधारणा है।

इस समय, वे या तो भारतीय संघवाद या स्विस संघवाद की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं। अब, यह कहाँ से आया? मुझे लगता है कि ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। चीन। हाँ, चीन का उत्तरी ईओ में से कुछ पर बहुत प्रभाव है। एक प्रकार से, इसका असर अराकान तक भी है क्योंकि उन्होंने चक्रवर्ती की सुरक्षा के लिए अराकान के साथ समझौता किया था। क्या भारत सीमा पार अपने ईओ के साथ भी ऐसा कर सकता है? क्या यह मध्यस्थ साझीदार हो सकता है? मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में एजेंसियों को खुद तय करना होगा।

साइबर स्कैम। साइबर स्कैम केवल बहुत अधिक पढ़े- लिखे लोगों को ही नहीं आकर्षित करते। जिन तीन लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, वे सभी कम पढ़े- लिखे थे लेकिन वे अंग्रेजी बोलते थे क्योंकि हर भारतीय थोड़ी- बहुत अंग्रेजी बोल लेता है। उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सोशल मीडिया पर जा सकें और मैसेज टाइप कर सकें। इन लोगों ने कभी विदेश यात्रा नहीं की थी। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। उन्हें लगा कि वे थाईलैंड जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। किस्मत अच्छी थी कि वे जिंदा बच गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आईटी प्रोफेशनल नहीं हैं।

यह बहुत मुश्किल हो जाता है। साइबर स्कैम के लिए चीन के साथ द्वीपक्षीय स्तर पर बात करना वास्तव में काम नहीं करेगा क्योंकि चीन ने खुद थ्री ब्रदरहुड अलायंस पर कार्रवाई की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए तत्माडॉ ने कोकांग इलाके में साइबर स्कैम पर कार्रवाई की, तभी वे मायावाड़ी चले गए। इसिलए चीन उनसे कोई लेना- देना नहीं रखना चाहता। शायद यह एक बहुपक्षीय मंच होना चाहिए, क्योंकि यह केवल हमें ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी प्रभावित करता है। इसका असर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और खुद म्यांमार पर भी पड़ता है। इसलिए इसे एक बहुपक्षीय मंच होना चाहिए। हमें खुफिया जानकारियों को साझा करने की आवश्यकता है। हमें अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे दूसरे देशों को भी इसमें शामिल करना होगा जो इससे प्रभावित हैं।

अंतिम बात, किसी ने वैधता की बात की थी। चुनाव, हम चाहे जितनी भी बहस करें कि यह वैध है या नहीं, यह वैधता का बहाना बन जाएगा। तो इसे वैधता मिलेगी। आधे आसियान देशों से इसे पहले ही वैधता मिल चुकी है। मलेशिया इसे वैधता नहीं देगा। अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिए हैं। यदि अमेरिका ऐसा करता है तो सिंगापुर भी करेगा, यूरोपीय संघ भी करेगा। हम इस पर बहस कर सकते हैं कि वैध है या नहीं। इसके अलावा, इससे उन्हें पहले से अधिक वैधता मिलेगी। मेरा जवाब पूरा हुआ। धन्यवाद।

प्रीत मलिक: बहुत- बहुत धन्यवाद। मैं पैनल के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ लेकिन क्या मैं बहुत कम समय लेते हुए कुछ बोल सकता हूँ, यहाँ पूछे गए सभी सवालों में से, और जो कुछ भी मैंने कहा और जो कुछ भी पैनल ने कहा, हममें से किसी ने भी एक ज़रूरी बात का उल्लेख नहीं किया। वह बात है कि बांग्लादेश में जो हुआ उससे भारत को कोई एक सबक लेना चाहिए था। तो वह सबक यह है कि आप केवल एक ही विकल्प पर निर्भर नहीं रह सकते। यह सबसे बड़े कारकों में से एक था जिस पर हमें बात करनी चाहिए थी। हममें से किसी ने भी इसका ज़िक्र नहीं किया। इसलिए मैं केवल इसका ज़िक्र भर कर रहा हूँ ताकि यह रिकॉर्ड में आ जाए। मुझे लगता है कि हमने

बहुत अधिक समय ले लिया है। इससे पता चलता है कि आज की चर्चा सार्थक रही। मुझे लगता है कि अब हमें जलपान के लिए प्रस्थान करना चाहिए।

अज्ञात वक्ता: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पैनल के सदस्यों, आप सभी का बहुत- बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत- बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से जलपान के लिए उपकक्ष की ओर प्रस्थान करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।